https://t.me/RausIAS https://t.me/RausIAS

FOUNDATION + CURRENT AFFAIRS

GENERAL STUDIES (PAPER –I)

FOUNDATION TEST –II

Test Code

FC19E1002

TOPIC: NCERT Polity Class XI-XII + Current Affairs

Time Allowed: 1½ Hours **Maximum Marks : 150**

अनुदेश

1. **परीक्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद, आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश, आदि न हो। यदि ऐसा है, तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लीजिए।**
2. इस परीक्षण पुस्तिका में **75** प्रश्नांश (प्रश्न) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश **हिन्दी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपा है प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिए गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए ***केवल एक ही*** प्रत्युत्तर चुनना है।
3. आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश देखिए।
4. ***सभी*** प्रश्नांशों के अंक समान हैं।
5. इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर-पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।
6. आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर ***केवल उत्तर-पत्रक*** अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।
7. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड :**

   प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा।

   (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक उस प्रश्न के लिए, जिसके लिए दंड है, दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक-तिहाई दंड के रूप में काटा जाएगा।

   (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही, उसी तरह का दंड दिया जाएगा, यदि उसके लिए दंड है।

   (iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

Q.1) भारत में स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकार के प्रावधान जोड़े गये थे।
2. भारतीय संविधान की दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ स्थानीय सरकार का प्रावधान करतीं हैं।
3. ग्राम पंचायत के पास यह शक्ति होती है, कि वह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन करने से इनकार कर सकती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 3
(c) केवल 2
(d) केवल 1 और 2

Q.2) निम्नलिखित में से कौन-से हमारे लोकतांत्रिक समाज में स्थापित मूल्यों का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं?

1. अर्थपूर्ण भागीदारी
2. जवाबदेही
3. अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता
4. असहमति का अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. "1793 के चार्टर अधिनियम" (The Charter Act of 1793) ने मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के तीन प्रेसीडेंसी नगरों में नगरपालिका प्रबंधन की स्थापना की थी।
2. 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जारी किये गए प्रस्ताव में स्थानीय सरकार का प्रावधान नहीं था।
3. "भारत सरकार अधिनियम, 1919" (The Government of India Act, 1919) के पश्चात कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

Q.4) निम्नलिखित में से कौन-से आदर्शों और सिद्धांतों को गांधीवादी दर्शन के साथ प्रतिष्ठापित कहा जा सकता है?

1. ग्राम गणतंत्र के आदर्श
2. शक्ति पदक्रम के निचले स्तर तक शक्ति का विकेंद्रीकरण
3. आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था
4. सहभागितापूर्ण लोकतंत्र

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.1) Which of the following statements about Local Government in India is/are correct?

1. The provisions of local government were added by the Constitution 42nd Amendment.
2. Tenth, Eleventh and Twelfth Schedule to the Indian Constitution provides for Local Government.
3. Gram Panchayat has the power to refuse allotment of land for commercial purpose.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 3 only
(b) 3 only
(c) 2 only
(d) 1 and 2 only

Q.2) Which of the following best describes the values enshrined in our democratic society?

1. Meaningful participation
2. Accountability
3. Absolute freedom of expression
4. Right to dissent

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 3 and 4 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 4 only
(d) 1, 2 and 3 only

Q.3) Consider the following statements:

1. The Charter Act of 1793 established municipal administration in the three presidency towns of Madras, Calcutta and Bombay.
2. Resolution issued by Lord Ripon in 1882 did not contain provision for local government.
3. Following the Government of India Act 1919, Village Panchayats were established in a number of provinces.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 3 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1, 2 and 3

Q.4) Which of the following ideals and principles can be said to be enshrined with Gandhian philosophy?

1. The ideals of village republic
2. Decentralization of power till the bottom of power hierarchy
3. Self-sustained village economy
4. Participatory democracy

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 3 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.5) प्रारम्भ में संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान में स्थानीय निकायों को शामिल नहीं किया गया था। इन्हे भारतीय संविधान में शामिल नहीं किए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारण माना जा सकता है/माने जा सकते हैं?

1. (विशेष रूप से) विभाजन के पश्चात चरम स्थानीयता से भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा
2. ग्रामीण समाज की जाति आधारित प्रकृति
3. भारतीय समाज में गुटवाद

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. "पी.के. थंगन समिति" (The P.K. Thungon Committee) ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है।
2. 'दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग' - "स्थानीय शासन"का प्रावधान नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.7) संविधान के 73वे और 74वे संशोधनों के पश्चात, संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा/से परिवर्तन किया गया था/किये गए थे?

1. सभी राज्यों में एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना होगी।
2. अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का सृजन, जिसमें पंचायत में रहने वाले सभी नागरिक सम्मिलित होंगें।
3. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल छह वर्ष होगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पंचायती राज संस्थानों के (सभी) तीनों स्तर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
2. राज्य सरकार के विघटन से राज्य में सभी पंचायतों का स्वतः विघटन हो जाता है।
3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, उनकी जनसँख्या के अनुपात में, (सभी) तीनों स्तरों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3
(b) केवल 1
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त में से भी कोई नहीं

Q.9) स्थानीय सरकार के स्तर पर दिए गए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सभी पंचायत संस्थानों में पदों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है।
2. आरक्षण तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के लिए भी लागू होता है।
3. महिलाओं के लिए सीटों में एक तिहाई आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों के अंतर्गत भी प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

Q.5) Local bodies were initially not included in the Indian Constitution by the Constituent Assembly. Which of the following can be attributed as a reason behind their non-inclusion in the Indian Constitution?

1. Extreme localism as a threat to unity and integrity of India especially after the Partition.
2. Cast-ridden nature of rural society.
3. Factionalism in Indian society.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 3 only
(c) 1 and 2
(d) 1, 2 and 3

Q.6) Consider the following statements:

1. P.K. Thungon Committee recommended constitutional recognition for the local government bodies.
2. Second Administrative Reform Commission does not provide for "Local Governance."

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.7) Which of the following changes was/were brought in the Constitution after Constitution 73rd and 74th Amendment?

1. All states to have a uniform three tier Panchayati Raj structure.
2. Mandatory creation of Gram Sabha comprising of all citizens residing in the Panchayat.
3. The term of each Panchayat to be fixed at six years.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3

Q.8) Consider the following statements:

1. All the three levels of Panchayati Raj institutions are elected directly by the people.
2. Dissolution of state government automatically leads to the dissolution of all panchayats in the state.
3. Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been provided at all the three levels in proportion to their population.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 3 only
(b) 1 only
(c) 1 and 3 only
(d) None of the above

Q.9) Consider the following statements regarding reservations provided at the level of local government:

1. One-third of the positions in all panchayat institutions are reserved for women.
2. Reservation also applies to the position of Chairpersons at the three levels.
3. Reservation of one-third of the seats for women is also provided within the seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward castes.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3

Q.10) 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से किन्हें "शहरी क्षेत्र"की विशेषताऐं कहा जा सकता है?

1. कार्यरत पुरुष जनसँख्या का कम से कम 75 प्रतिशत गैर-कृषि व्यवसायों में कार्यरत है।
2. कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसँख्या घनत्व।
3. न्यूनतम 5000 जनसँख्या।
4. वे सभी स्थान जिनमें नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित शहर क्षेत्र समिति हो।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.11) निम्नलिखित में से कौन-से सकारात्मक गुणों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व-सरकार के गुण माना जा सकता है?

1. लोगों की भागीदारी में वृद्धि
2. अल्पसंख्यक धर्म के नागरिकों का बढ़ता प्रतिनिधित्व
3. महिला सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप स्थानीय मुद्दों की संवेदनशीलता में अग्रणीयता
4. वित्तीय सहायता के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भरता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 3 और 4

Q.12) अमेरिकी संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है?

1. मौलिक अधिकार
2. अवशिष्ट शक्तियों का विचार
3. न्यायिक समीक्षा की शक्ति
4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.13) निम्नलिखित में से किन्हें संविधान के कार्यों के रूप में माना जा सकता है?

1. समाज के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की अनुमति देना।
2. यह तय करना कि कानून का निर्माण कौन करेगा।
3. सरकार की सीमाऐं अधिरोपित करना।
4. समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.14) भारतीय संविधान को "एक जीवित दस्तावेज़" (A Living Document) क्यों माना जाता है?

(a) यह लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
(b) यह कठोरता और लचीलेपन (नम्यता) के बीच संतुलन स्थापित करता है।
(c) संसद की संविधान में संशोधन करने की अक्षमता।

(d) **संसद की संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन करने की क्षमता |**

Q.10) Which of the following can be said to be feature/s of *"urban areas"* as per the Census of 2011?

1. At least 75 per cent of the male working population engaged in non-agricultural occupations.
2. Density of population of at least 400 persons per sq. km.
3. Minimum population of 5000
4. All places with a municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 2 and 3 only
(b) 1 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.11) Which of the following can be said to be the positives of Local Self-Government in rural and urban areas?

1. Increased people's participation
2. Increased representation of citizens from minority religions
3. Women empowerment leading to sensitizing of local issues
4. Dependence on state and central government for financial support.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 3 only
(b) 2 and 4 only
(c) 1 and 2 only
(d) 3 and 4 only

Q.12) Which of the following features of the Indian Constitution have been borrowed from the USA's Constitution?

1. Fundamental Rights
2. Idea of Residuary Powers
3. Power of Judicial Review
4. Independence of Judiciary

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.13) Which among the following can be considered as functions of the Constitution?

1. Allow for coordination amongst the members of a society.
2. To decide who shall make the Laws.
3. Impose limits on the Government.
4. Fulfil the aspirations of a society.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 3 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.14) Why is the Indian Constitution considered as "a living document"?

(a) It seeks to ensure livelihood of the people.
(b) It strikes a balance between rigidity and flexibility.
(c) Inability of the Parliament to amend the constitution.
(d) Ability of the Parliament to amend all the provisions of the constitution.

Q.15) भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा/से "धर्म की स्वतंत्रता" के पहलु/पहलुओं के रूप में जाना जाता है/जाने जाते हैं?

1. किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार
2. किसी भी धर्म का पालन नहीं करने का अधिकार
3. किसी भी धर्म के प्रचार का अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.16) सरकार किसी वृत्तचित्र (Documentary Film), जिसमें उसकी नीतियों की आलोचना की गई है, पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है। इस मामले में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है?

(a) समानता का अधिकार
(b) स्वाधीनता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
(c) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(d) सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

Q.17) सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट आदेश जारी किया है, जिसमें उसने "केंद्रीय जांच ब्यूरो" (The Central Bureau of Investigation – CBI) को भ्रष्टाचार के एक उच्च प्रोफ़ाइल मामले की जांच, एक निश्चित समय सीमा में, पूरी करने के लिए कहा है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी "रिट" (Writ) जारी की जा सकती है?

(a) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
(b) परमादेश (Mandamus)
(c) निषेध (Prohibition)
(d) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

Q.18) "संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार" (The Fundamental Right to Constitutional Remedies) को "संविधान का हृदय और आत्मा" (The Heart and Soul of the Constitution) क्यों माना जाता है?

1. यह अधिकार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का प्रावधान करता है।
2. मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी न्यायालय के पास जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.19) भारत में निम्नलिखित में से कौन-से अल्पसंख्यकों को "सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों" के मौलिक अधिकार के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है?

1. धार्मिक अल्पसंख्यक
2. भाषाई अल्पसंख्यक
3. सांस्कृतिक अल्पसंख्यक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.20) संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार गैर-न्यायोचित अधिकार हैं?

1. शिक्षा का अधिकार
2. समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार
3. काम करने का अधिकार
4. पर्याप्त आजीविका का अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.15) Which among the following is/are considered as aspects of Freedom of Religion under the Indian Constitution?

1. Right to follow any religion.
2. Right not to follow any religion.
3. Right to propagate any religion.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.16) The Government decides to ban a documentary film which has been critical of its policies. Which among the following Fundamental rights is violated in this case?

(a) Right to Equality
(b) Right to Liberty and Personal Freedom
(c) Right against Exploitation
(d) Cultural and Educational Rights

Q.17) The Supreme Court passes a writ order asking the CBI to complete the investigation of a high-profile corruption case within a time-bound manner. Which of the following "Writ" can be issued by the Supreme Court in this case?

(a) Habeas Corpus
(b) Mandamus
(c) Prohibition
(d) Quo Warranto

Q.18) Why is the Fundamental Right to Constitutional Remedies considered as "Heart and Soul of the Constitution"?

1. This right provides for the enforcement of the Fundamental Rights.
2. In case of violation of Fundamental Right, an individual can approach any court in India.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.19) Which among the following minorities in India have been given protection under the Fundamental right of Cultural and Educational Rights?

1. Religious Minorities
2. Linguistic Minorities
3. Cultural Minorities

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.20) Which among the following is/are non-justiciable rights under the Constitution?

1. Right to Education
2. Equal pay for equal work
3. Right to work
4. Right to Adequate livelihood

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.21) चुनाव में "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली" (The Proportional Representation System) की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?

1. पूरा देश एकल निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है।
2. मतदाता उम्मीदवार के स्थान पर पार्टी को वोट देता है।
3. विधायिका में सीटों की संख्या राजनीतिक दल को मिले मतों के प्रतिशत पर आधारित होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.22) भारत में चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में सभी चुनाव "फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट" (First Past The Post - FPTP) प्रणाली पर आधारित हैं।
2. भारत का निर्वाचन आयोग, स्थानीय निकायों के चुनावों सहित, भारत के सभी चुनावों का आयोजन और पर्यवेक्षण करता है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों की शक्तियाँ समान होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

Q.23) भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आधार/किन आधारों पर राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है?

1. संविधान का उल्लंघन
2. सिद्ध कदाचार या अक्षमता
3. अनुन्मुक्त दिवालियापन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.24) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों की परिषद के आकार को सही रूप से प्रदर्शित करता है?

(a) जनता के सदन (लोक सभा) के कुल सदस्यों का 10% से कम
(b) जनता के सदन (लोक सभा) के कुल सदस्यों का 15% से कम
(c) संसद के कुल सदस्यों का 10% से कम
(d) संसद के कुल सदस्यों का 15% से कम

Q.25) "दल-बदल रोधी कानून" (The Anti-Defection Law) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा/से संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए आधार है/हैं?

1. यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से पार्टी से इस्तीफा दे देता है।
2. यदि कोई सदस्य, पार्टी के द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.26) धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन वह इसमें केवल संशोधन कर सकती है।
3. असहमति की स्थिति में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q.21) Which among the following are the features of Proportional Representation system of Election?

1. The entire country may be a single constituency.
2. The voter votes for the party instead of a candidate.
3. The seats in the legislature is based on the percentage of votes that a political party gets.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.22) Consider the following statements related to Elections in India:

1. All the elections in India are based on First Past The Post (FPTP) system.
2. The Election commission of India conducts and supervises all the elections in India, including the elections for local bodies.
3. The Chief Election Commissioners and other two election commissioners enjoy equal powers.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.23) On which of the following grounds can the President be impeached under the Indian Constitution?

1. Violation of Constitution
2. Proved Misbehaviour or Incapacity
3. Undischarged insolvency

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.24) Which among the following correctly depicts the size of the Council of Ministers under the 91st Amendment Act?

(a) Shall not exceed 10% of the total members of the House of People
(b) Shall not exceed 15% of the total members of the House of People
(c) Shall not exceed 10% of the total members of the Parliament
(d) Shall not exceed 15% of the total members of the Parliament

Q.25) Which among the following is/are grounds for disqualification of Members of Parliament under the Anti-Defection?

1. If a member voluntarily resigns from the party.
2. If a member votes against the instructions issued by the party.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.26) Consider the following statements related to Money Bill:

1. The Money bill can be introduced only in Lok Sabha.
2. The Rajya Sabha cannot reject the Money Bill, but it can only make amendments.
3. In case of disagreement, there is a provision for joint sitting of both the houses of Parliament.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.27) भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से क्षेत्रों से राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन के लिए विचार किया जा सकता है?

1. कला
2. साहित्य
3. विज्ञान
4. सामाजिक सेवा
5. सहकारी आंदोलन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.28) निम्नलिखित मामलों में से कौन-सा मामला/कौन-से मामले केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही सुने जा सकता है/सकते हैं, उच्च न्यायालयों के द्वारा नहीं?

1. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
2. कानून की संवैधानिकता निर्धारित करना
3. केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

Q.29) न्यायपालिका की स्वंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएं प्रदान की गई हैं?

1. न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा।
2. न्यायपालिका, वित्तीय रूप से, न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका पर निर्भर है।
3. न्यायपालिका को "न्यायालय की अवमानना" के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
4. संसद को, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, न्यायाधीशों के आचरण के बारे में चर्चा करने पर निषेध।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.30) जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनहित याचिकाओं ने भारत में न्यायालयों पर अत्यधिक कार्यभार डाला है।
2. जनहित याचिकाओं ने भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.27) Which among the following fields can be considered for the nomination of members to the Rajya Sabha under the Indian Constitution?

1. Art
2. Literature
3. Science
4. Social Service
5. Cooperative Movement

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 1, 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3, 4 and 5

Q.28) Which among the following cases can be heard only by the Supreme Court and not by high courts?

1. Violation of Fundamental Rights
2. To ascertain constitutionality of law
3. Dispute involving Centre and State

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.29) Which among the following features have been provided under the Indian Constitution to ensure the Independence of Judiciary?

1. Security of Tenure for the Judges.
2. The Judiciary is not financially dependent on either the executive or the legislature.
3. Power of the Judiciary to punish for the Contempt of Court
4. Restraining the Parliament from discussing about the conduct of the Judges except under certain circumstances.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1, 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.30) Consider the following statements related to Public Interest Litigation (PIL):

1. PILs have overburdened the courts in India.
2. PILs have expanded the scope of democratic rights in India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.31) निम्नलिखित में से किस को/किन-किन को "न्यायिक सक्रियता" (Judicial Activism) के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है?

1. कानून की संवैधानिकता पर सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना।
2. सार्वजनिक महत्व से संबंधित किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद को आदेश देना।
3. भ्रष्टाचार के मामले में राजनेताओं के विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए "केंद्रीय जांच ब्यूरो" (The Central Bureau of Investigation – CBI) को दिशानिर्देश देना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.32) निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में संघवाद की विशेषताएं हैं?

1. एकल नागरिकता।
2. अवशिष्ट शक्तियों पर राज्यों का नियंत्रण।
3. केंद्र के द्वारा राज्य की सहमति के बिना ही उसकी (राज्य की) सीमाओं में परिवर्तन करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2
(d) केवल 1 और 3

Q.33) भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में से कौन-से विषय राज्य सूची के भाग हैं?

1. शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) तथा वायदा बाजार (फ्यूचर मार्केट्स)
2. शर्त लगाना तथा जुआ खेलना
3. स्वास्थ्य
4. पुलिस

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4

Q.34) संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन-से प्रावधान एक सुदृढ़ संघ सरकार के साथ संघवाद प्रदान करते हैं?

1. केंद्र के द्वारा आपातकाल की घोषणा।
2. कुछ परिस्थितियों में संघ की राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति।
3. संघ की राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति।
4. अखिल भारतीय सेवाएं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.31) Which of the following options can be considered as instances of Judicial Activism?

1. Deliberation of the Supreme Court on the Constitutionality of law.
2. Ordering the Parliament to make a law on a matter relating to Public importance.
3. Giving directions to the CBI to initiate investigations against politicians in corruption case.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Q.32) Which among the following are the features of Federalism in India?

1. Single Citizenship.
2. Residuary powers are vested in state Legislature.
3. Alteration in the boundaries of the state by the centre without its consent.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only

(b) 3 only

(c) 2 only

(d) 1 and 3 only

Q.33) Which among the following subjects are part of state list under the Indian Constitution?

1. Stock exchanges and futures markets
2. Betting and gambling
3. Health
4. Police

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only

(b) 1, 2 and 3 only

(c) 3 and 4 only

(d) 2, 3 and 4 only

Q.34) Which among the following provisions of the constitution provide for Federalism with a strong Union government?

1. Declaration of Emergency by the centre.
2. Power of the Union to legislate on the state list under certain circumstances.
3. Power of the Union to issue instructions to the state government.
4. All India Services

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only

(b) 1 and 3 only

(c) 1, 2 and 3 only

(d) 1, 2, 3 and 4

Q.35) रियासतों (Princely States) और उनके एकीकरण के माध्यमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

1. जूनागढ़ - विलय समझौता
2. मणिपुर - जनमत संग्रह
3. हैदराबाद - सैन्य हस्तक्षेप

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

Q.36) भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. स्वतन्त्रता के बाद देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए "भाषा" मुख्य मानदंडों में से एक रही है।
2. स्वतन्त्रता के बाद निर्मित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.37) राजनीतिक दलों और उनके संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

1. भारतीय जन संघ - श्यामा प्रसाद मुखर्जी
2. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी – ए. के. गोपालन
3. स्वतंत्र पार्टी – सी. राजगोपालाचारी
4. सोशलिस्ट पार्टी - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.38) निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था?

(a) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
(b) राजकुमारी अमृत कौर
(c) सी. राजगोपालाचारी
(d) ए. के. गोपालन

Q.39) स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. पंच वर्षीय योजना के मॉडल को पूर्व सोवियत संघ से अपनाया गया था।
2. योजना आयोग को, भारत के विकास के मॉडल के लिए योजना तैयार करने हेतु, एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
3. दूसरी पंच वर्षीय योजना का संकेद्रण (फोकस) भारी उद्योगों पर था।
4. के. एन. राज प्रथम पंच वर्षीय योजना के निर्माता थे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2, और 3
(d) केवल 1, 3 और 4

Q.40) भारत तथा इसके अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित विभिन्न समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

1. शिमला समझौता - भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965
2. बांडुंग सम्मेलन (The Bandung Conference) - एफ्रो-एशिया एकता, 1955
3. ताशकंद समझौता - भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q.35) With reference to the princely states and their means of integration, which of the pairs are correctly matched?

1. Junagarh – Merger agreement
2. Manipur – Plebiscite
3. Hyderabad – Army intervention

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 3 only
(d) 2 and 3 only

Q.36) With reference to reorganization of states in India, which of the following statements is/are correct?

1. Language has been one of the main criteria for reorganization of states in the post-independence India.
2. Andhra Pradesh was the first state to be created after independence.

Select the correct answer using code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.37) With reference to political parties and their founders, which of the following have been correctly matched?

1.	Bharatiya Jana Sangh	-	Shyama Prasad Mukherjee
2.	Independent Labour party	-	A.K Gopalan
3.	Swatantra Party	-	C. Rajagopalac-hari
4.	Socialist Party	-	Dr B.R. Ambedkar

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 1 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.38) Who amongst the following was not a member of the Constituent Assembly?

(a) Maulana Abul Kalam Azad
(b) Rajkumari Amrit Kaur
(c) C Rajagopalachari
(d) A.K Gopalan

Q.39) With reference to planned development in India post-independence, which of the following statements is /are correct?

1. The Five Year Plan Model was adopted from the erstwhile Soviet Union.
2. The Planning commission was set up as a constitutional body to prepare a plan for India's development model.
3. 2nd Five Year Plan focused on heavy industries.
4. K.N Raj was the architect of the 1st Five Year Plan.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1, 2, and 3 only
(d) 1, 3 and 4 only

Q.40) With reference to India and various agreements signed by it with other countries, which of the following pairs is/are correctly matched?

1.	Shimla Agreement	-	India Pakistan War 1965
2.	Bandung Conference	-	Afro-Asia unity, 1955
3.	Tashkent Agreement	-	India Pakistan War 1971

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.41) भारत के संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में किसे/किन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है?

1. संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें (The Recommendations of the Union Finance Commission)
2. लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (The Report of the Public Accounts Committee)
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (The Report of the Comptroller and Auditor General)
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट (The Report of the National Commission for Scheduled Castes)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Q.42) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
2. चुनाव सम्बन्धी विवादों का निर्णय करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है।
3. भारत के संविधान के अनुसार, संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही शामिल होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q.43) निम्नलिखित में से कौन-सी/सीं भारत सरकार अधिनियम, 1919 (The Government of India Act, 1919) की मुख्य विशेषता/विशेषताऐं है/हैं?

1. प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन-प्रणाली की शुरुआत।
2. मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.44) भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन-से प्रावधान शिक्षा का वहन करते हैं?

1. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (The Directive Principles of State Policy)
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पांचवीं अनुसूची
4. सातवीं अनुसूची

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 1, 2 और 4

Q.45) यदि राज्यसभा के द्वारा किसी धन विधेयक में मूलत: संशोधन किया गया है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा?

(a) लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करके या स्वीकार किये बिना ही विधेयक की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती है।
(b) लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती है।
(c) लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा के पास भेज सकती है।
(d) राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है।

Q.41) According to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following?

1. The Recommendations of the Union Finance Commission
2. The Report of the Public Accounts Committee
3. The Report of the Comptroller and Auditor General
4. The Report of the National Commission for Scheduled Castes

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

Q.42) Consider the following statements:

1. Union Territories are not represented in the Rajya Sabha.
2. It is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate the election disputes.
3. According to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and the Rajya Sabha only.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) None of the above

Q.43) Which of the following is/are the principal feature(s) of the Government of India Act, 1919?

1. Introduction of dyarchy in the executive government of the provinces.
2. Introduction of separate communal electorates for Muslims.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.44) Which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on Education?

1. Directive Principles of State Policy
2. Rural and Urban Local Bodies
3. Fifth Schedule
4. Seventh Schedule

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 4 only

Q.45) What will follow if a Money Bill is substantially amended by the Rajya Sabha?

(a) The Lok Sabha may still proceed with the Bill, accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha
(b) The Lok Sabha cannot consider the Bill further
(c) The Lok Sabha may send the Bill to the Rajya Sabha for reconsideration
(d) The President may call a joint sitting for passing the Bill

Q.46) "आर्थिक न्याय" भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक है। इसका प्रावधान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है?

(a) प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में
(b) प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में
(c) मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में
(d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

Q.47) भारत के संविधान के अनुसार, देश के अभिशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन-से मूल तत्त्व हैं?

(a) मौलिक अधिकार
(b) मौलिक कर्तव्य
(c) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
(d) मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य

Q.48) भारत में "अविश्वास प्रस्ताव" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.49) निम्नलिखित समितियों में से कौन-सी संसद की सबसे बड़ी समिति है?

(a) लोक लेखा समिति (The Committee on Public Accounts)
(b) प्राक्लन समिति (The Committee on Estimates)
(c) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (The Committee on Public Undertakings)
(d) याचिकाओं पर समिति (The Committee on Petitions)

Q.50) भारत की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है?

(a) भारत के राष्ट्रपति में
(b) संसद में
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश में
(d) विधि आयोग में

Q.51) "मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018" [The Protection of Human Rights (Amendments) Bill, 2018] के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग" (The National Human Rights Commission) के एक मान्य सदस्य के रूप में "बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग" (The National Commission for Protection of Child Rights) को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखता है।
2. इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए एक तंत्र को समाविष्ट करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.46) 'Economic Justice' as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in:

(a) the Preamble and Fundamental Rights

(b) the Preamble and the Directive Principles of State Policy

(c) the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy

(d) None of the above

Q.47) According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country?

(a) Fundamental Rights

(b) Fundamental Duties

(c) Directive Principles of State Policy

(d) Fundamental Rights and Fundamental Duties

Q.48) Consider the following statements regarding a No-Confidence Motion in India:

1. There is no mention of a No-Confidence Motion in the Constitution of India.
2. A Motion of No-Confidence can be introduced in the Lok Sabha only.

Which of the statements given above is / are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

Q.49) Which one of the following is the largest Committee of the Parliament?

(a) The Committee on Public Accounts

(b) The Committee on Estimates

(c) The Committee on Public Undertakings

(d) The Committee on Petitions

Q.50) The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in

(a) the President of India

(b) the Parliament

(c) the Chief Justice of India

(d) the Law Commission

Q.51) Consider the following statements about the Protection of Human Rights (Amendments) Bill, 2018:

1. It proposes to include "National Commission for Protection of Child Rights" as deemed Member of the National Human Right Commission.
2. It aims to incorporate a mechanism to look after the cases of human rights violation in the Union Territories.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

Q.52) "महिला शक्ति केंद्र योजना" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आरम्भ की गई थी।
2. यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
3. इसका उद्देश्य, ग्रामीण और शहरी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें वे अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से वास्तविक बना सकें/ प्राप्त कर सकें।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 3
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q.53) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा "स्वाधार गृह योजना" का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो बाल यौन शोषण पीड़ितों को लक्षित करती है।
2. इस योजना में पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य के अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.54) नीति आयोग के द्वारा जारी की गई "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" (Healthy States, Progressive India नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तकनीकी सहयोग से, विकसित की गई है?
2. यह स्वास्थ्य सूचकांक, स्वास्थ्य सम्बन्धी परिणामों को प्राप्त करने की गति को तीव्र करने के लिए, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने हेतु, एक साधन के रूप में विकसित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.55) "पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच"(The NITI Forum for North-East) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में, त्वरित, समावेशी और सतत (धारणीय) आर्थिक विकास के मार्ग पर विभिन्न बाधाओं की पहचान करने के लिए इस मंच की स्थापना की गई थी।
2. इस मंच की पहली बैठक असम में आयोजित की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.52) Which of the following statements is/are correct about Mahila Shakti Kendra Scheme?

1. It was introduced by the Ministry of health and family welfare.
2. The scheme is fully funded by the central government.
3. It aims at empowering rural and urban women through community participation to create an environment in which they can realize their full potential.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 3 only
(b) 1 and 3 only
(c) 1 and 2 only
(d) None of the above

Q.53) Consider the following statements:

1. The Ministry of Women and Child Development is implementing the Swadhar Greh Scheme which targets the victims of child sexual abuse.
2. The Scheme envisages providing shelter, food, clothing and health as well as economic and social security for women victims.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.54) Which of the following statements is/are correct about a comprehensive Health Index report titled, "Healthy States, Progressive India" released by NITI Aayog?

1. It has been developed by NITI Aayog, with technical assistance from the International Monetary Fund.
2. This Health Index has been developed as a tool to leverage co-operative and competitive federalism to accelerate the pace of achieving health outcomes.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.55) Consider the following statements about the 'NITI Forum for Northeast':

1. 'The NITI Forum for Northeast' was set up to identify various constraints on the way of accelerated, inclusive and sustainable economic growth in the North-East Region of the country.
2. The first meeting of the forum was held in Assam.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.56) अभी हाल ही में आरम्भ किये गए "UPaAI" (Unified Planning and Analysis Interface) एप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह सांसदों को उनके राज्यों में विकास कार्यों की निगरानी करने में सहायता करेगा।
2. यह एप लगभग 500 केंद्रीय योजनाओं और "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष" (The MP Local Area Development – MPLAD – Fund) की भी जानकारी प्रदान करेगा।
3. यह नीति आयोग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया था।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

Q.57) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय के, मुख्य न्यायाधीश के अलावा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।
2. प्रधानमंत्री की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और पुष्टि की विधि दूसरी अनुसूची में दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q.58) "भारत की गुणवत्ता परिषद" (The Quality Council of Indi(a) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे भारत सरकार और भारतीय उद्योग संघों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
2. यह परिषद "कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय" (The Ministry of Corporate Affairs) के प्रशासन के अधीन संचालित होती है।
3. यह परिषद भारत के उद्यमों, विशेषतौर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है।
4. यह परिषद विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए "राष्ट्रीय मान्यता कार्यक्रमों" (The National Accreditation Programmes) को विकसित करने, स्थापित करने और संचालित करने में सहायता करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

Q.59) निम्नलिखित में से कौन-से कार्य "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" (The National Council on Vocational Training - NCVT) के द्वारा निष्पादित कार्य कहे जा सकते हैं?

1. "राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र" (The National Trade Certificates) प्रदान करने के उद्देश्य से केवल निजी एजेंसियों के द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करना।
2. राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए योग्यता के मानकों और शर्तों को निर्धारित करना।
3. क्षमता के मानकों, पाठ्यक्रमों की संरचना, क्रेडिट संरचना और प्रमाणीकरण के लिए तंत्र को सूत्रबद्ध करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 2 और 3

(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.56) Which of the following statements is/are correct about recently launched 'UPaAI App' (Unified planning and analysis interface)?

1. It will help the Members of parliament to track the development work in their states.
2. The app will also provide information on about 500 Central schemes and MP local area development (MPLAD) fund.
3. It was developed by NITI Ayog and the Ministry of information and technology.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1, 2 and 3

Q.57) Consider the following statements:

1. In case of appointment of Judge of Supreme Court other than Chief Justice, it is not mandatory to consult Chief Justice of India in such appointments.
2. A distinguished Jurist in the opinion of the Prime Minister can be appointed as Judge of Supreme Court.
3. Form of oath and affirmation to be made by Judges of Supreme Court has been provided in the Second Schedule.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 3 only
(d) None of the above

Q.58) Consider the following statements about Quality Council of India:

1. It is set up jointly by the Government of India and the Indian Industry Associations.
2. It operates under the administration of Ministry of Corporate Affairs.
3. It promotes quality competitiveness of India's enterprises especially MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises).
4. It helps to develop, establish and operate National Accreditation Programmes for various service sectors.

Which of the statements given above are correct?

(a) 3 and 4 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2 and 3 only

Q.59) Which of the following can be said to be the functions performed by National Council on Vocational Training (NCVT)?

1. Recognize training institutions run only by private agencies for purposes of the grant of National Trade Certificates.
2. To prescribe the standards and conditions of eligibility for the award of National Trade Certificates.
3. To formulate framework for competency standards, structure of courses, credit structure and certification.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 2 and 3 only
(b) 1 and 2 only

(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.60) **राज्यसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **उपाध्यक्ष को केवल राज्यों की परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा।**
2. **राज्यों की परिषद के उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाले सदस्य को अपना पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि उसकी राज्यों की परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाती है।**
3. **राज्यों की परिषद के सभी वर्तमान सदस्य, बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) **केवल** 1 **और** 2
(b) **केवल** 1 **और** 3
(c) **केवल** 3
(d) 1, 2 **और** 3

Q.61) **सरकार ने अभी हाल ही में एक विज़न दस्तावेज़** (A Vision Document) – "**डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विज़न** 2022" (Digital North East Vision 2022) **जारी किया है। इस विज़न दस्तावेज़ के लक्ष्य हैं:**

1. **क्षमता का निर्माण करना**
2. **जीवन जीने की सुगमता में वृद्धि करना**
3. **क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए "राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर"** (The National Register of Citizens) **तैयार करना**
4. **क्षेत्र की डिजिटल आधारिक संरचना और डिजिटल सेवाओं में सुधार करना**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) **केवल** 1 **और** 3
(b) **केवल** 1, 2 **और** 4
(c) **केवल** 3 **और** 4
(d) **केवल** 1, 3 **और** 4

Q.62) **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **दिल्ली उच्च न्यायालय ने, अभी अपने हाल ही के एक निर्णय में, सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने का अपराधीकरण कर दिया है।**
2. **भीख मांगने में सार्वजनिक स्थान पर दान का आग्रह करना अथवा प्राप्त करना शामिल हैं |**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) **केवल** 1
(b) **केवल** 2
(c) 1 **और** 2 **दोनों**
(d) **न तो** 1, **न ही** 2

Q.63) "**स्मार्ट सिटीज़ मिशन**, 2015" (The Smart Cities Mission, 2015) **के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **यह "आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय"** (The Ministry of Housing and Urban Affairs) **के द्वारा शुरू किया गया है।**
2. **स्मार्ट शहरों के चयन की प्रक्रिया "प्रतिस्पर्धी संघवाद"**(Competitive Federalism) **के विचार पर आधारित है।**
3. **यह मिशन शहरों की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसँख्या को सुविधाजनक बनाएगा।**
4. **इसका उद्देश्य सभी के लिए, विशेष रूप से निर्धनों और वंचित लोगों के लिए, रोज़गार पैदा करना और आय बढ़ाना है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) **केवल** 2 **और** 3

(b) **केवल** 2, 3 **और** 4

(c) **केवल** 1, 3 **और** 4

(d) 1, 2, 3 **और** 4

Q.60) Consider the following statements about Deputy Chairman of Rajya Sabha:

1. Deputy Chairman shall be elected by members of Council of States only.
2. A member holding the office of Deputy Chairman of Council of States need not necessarily vacate his/her office if he/she ceases to be member of the Council of States.
3. Deputy Chairman may be removed from his office if the Council of States passes a resolution by a majority of all the then members of the Council.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 1 and 3 only

(c) 3 only

(d) 1, 2 and 3

Q.61) The government has recently released a vision document - 'Digital North East Vision 2022'. The vision document aims at:

1. Capacity Building
2. Enhance ease of living
3. Prepare National Register of Citizens for all individuals residing in the region.
4. Improve digital infrastructure and digital services of the region.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 3

(b) 1, 2 and 4

(c) 3 and 4

(d) 1, 3 and 4

Q.62) Consider the following statements:

1. Delhi High Court in a recent judgment has criminalized the act of begging in public place.
2. Begging includes soliciting or receiving alms in a public place.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

Q.63) Consider the following statements about Smart Cities Mission, 2015:

1. It has been launched by Ministry of Housing and Urban Affairs.
2. The selection process of Smart Cities is based on the idea of Competitive Federalism.
3. It will facilitate rapidly expanding population of cities.
4. It aims to create employment and enhance incomes for all, especially the poor and the disadvantaged.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 2 and 3 only

(b) 2, 3 and 4 only

(c) 1, 3 and 4 only

(d) 1, 2, 3 and 4

Q.64) "**इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड**" (The Integrated Theatre Command) **के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **यह एक (अकेले) कमांडर के अधीन तीनों सेवाओं की एक एकीकृत कमांड की परिकल्पना करती है।**
2. **"इंटीग्रेटेड थियेटर कमांडर"** (The Integrated Theatre Commander) **व्यक्तिगत सेवाओं के प्रति उत्तरदायी होगा।**
3. **शेकटकर समिति ने चीन की सीमा, पाकिस्तान की सीमा और समुद्री सुरक्षा के लिए तीन इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड के निर्माण की सिफारिश की है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) **केवल** 1 **और** 2

(b) **केवल** 1 **और** 3

(c) **केवल** 2 **और** 3

(d) 1, 2 **और** 3

Q.65) **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **अनुच्छेद**-35A **जम्मू-कश्मीर के निवासियों को स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करता है।**
2. **अनुच्छेद**-35A **को भारतीय संविधान में अनुच्छेद**-368 **के तहत एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।**
3. **संविधान की मूल संरचना को संसद या कार्यपालिका के द्वारा बदला अथवा संशोधित नहीं किया जा सकता है।**
4. **संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए संसद को असीमित शक्ति प्राप्त है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) **केवल** 1 **और** 2

(b) **केवल** 3 **और** 4

(c) **केवल** 1 **और** 3

(d) **केवल** 2 **और** 4

Q.66) **भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों** (The Public Sector Banks - PSBs) **के पुर्नोत्थान के लिए "इंद्रधनुष योजना" के घटक निम्नलिखित में से कौन-से हैं?**

1. **बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना**
2. **बैंकों का पूंजीकरण**
3. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश**
4. **बैंकों की गैर-निष्पादिक परिसंपत्तियों** (The Non-Performing Assets – NPAs) **को कम करना**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) **केवल** 1 **और** 2

(b) **केवल** 1, 2 **और** 4

(c) **केवल** 2 **और** 4

(d) 1, 2, 3 **और** 4

Q.67) "**प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान**" (Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan – PMJAA **के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **यह स्वास्थ्य बीमा योजना** 5 **लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की निःशुल्क कवरेज प्रदान करती है।**
2. **इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर पहचाना जाना है।**
3. **इस योजना में नैदानिक परीक्षण (चिकित्सीय जांच) और दवाओं जैसे बाहरी खर्चों के लिए भी बीमा शामिल है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) **केवल** 1

(b) **केवल** 1 **और** 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q.64) Consider the following statements about "Integrated Theatre Command":

1. It envisages a unified command of three services under a single commander.
2. The integrated theatre commander will be answerable to individual services.
3. Shekatkar Committee recommended creation of three integrated theatre command along China border, Pakistan border and for maritime security.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 1 and 3 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Q.65) Consider the following statements:

1. Article 35A grants the status of permanent residency to the residents of Jammu and Kashmir.
2. Article 35A was added to the Indian Constitution through an amendment under Article 368.
3. Basic Structure of the Constitution cannot be altered or amended by the Parliament or the Executive.
4. Parliament enjoys unlimited power to amend any provision of the constitution.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2

(b) 3 and 4

(c) 1 and 3

(d) 2 and 4

Q.66) Which among the following are the components of Indradhanush plan for revamping the Public Sector Banks (PSBs) in India?

1. Setting up of Bank Board Bureau
2. Capitalisation of the Banks
3. Disinvestment of Public Sector Banks
4. Reducing the NPAs (Non-Performing Assets) of Banks

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only

(b) 1, 2 and 4 only

(c) 2 and 4 only

(d) 1, 2, 3 and 4

Q.67) Consider the following statements related to Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan (PMJAA):

1. This health insurance scheme provides free coverage of upto Rs 5 lakh per family per year.
2. The beneficiaries under the scheme are to be identified based on Socio-Economic Caste Census (SECC).
3. The scheme covers insurance for outpatient expenses such as diagnostic tests and medicines.

Which statements given above is/are correct?

(a) 1 only

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1,2 and 3

Q.68) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण नीति, 2017" (The National Health Protection Policy, 2017) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकार के व्यय को "सकल घरेलू उत्पाद" (Gross Domestic Product – GDP) का 2.5% तक बढ़ाना है।
2. यह नीति क्रमशः प्राथमिक देखभाल, माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए संसाधनों के प्रमुख अनुपात को आवंटित करने का समर्थन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q.69) "एक दुनिया अनेक आवाज़" निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित है?

(a) सभी भारतीयों को जोड़ने के लिए विदेश मंत्रालय की पहल।
(b) दक्षिण एशिया में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को जोड़ने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल।
(c) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातियों तक पहुंचने के लिए गृह मंत्रालय की योजना।
(d) सभी बौद्धों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजना।

Q.70) अभी हाल ही में समाचारों में चर्चित "एशियन प्रीमियम" (The Asian Premium) निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित है?

(a) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एशियाई देशों द्वारा अतिरिक्त लागत का वहन।
(b) "ओपेक"(OPEC – The Organisation of Petroleum Exporting Countries) देशों के द्वारा, एशियाई देशों से तेल की बिक्री पर वसूला जा रहा अतिरिक्त मूल्य/लागत।
(c) "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष" (The International Monetary Fund – IMF) में भारत और चीन को अतिरिक्त कोटा का प्रावधान।
(d) "विश्व व्यापार संगठन" (The World Trade Organisation – WTO) के द्वारा एशियाई देशों को दिए गए अतिरिक्त विशेषाधिकार।

Q.71) "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण" (The Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) अधिनियम, 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. त्वरित सुनवाई के लिए "पॉक्सो" (POCSO) विशेष अदालतों की स्थापना की निगरानी करने हेतु सम्बंधित राज्यों की उच्च न्यायालयों को अधिदिष्ट किया गया है।
2. यह अधिनियम झूठी रिपोर्टिंग के लिए छह महीने के दंड का प्रावधान करता है।
3. इस अधिनियम के अंतर्गत केवल पुरुषों के विरुद्ध ही सुनवाई हो सकती है और उन्हें दंडित किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.72) भारत में जेल सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. भारत में जेल प्रणाली का आधुनिकीकरण और सुधार टी. बी. मैकॉले (T.B. Macaulay) के द्वारा आरम्भ किये गये थे।
2. "जेल" भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची - III के तहत एक समवर्ती सूची का विषय है।
3. न्यायमूर्ति मुल्ला और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समितियाँ, स्वतंत्रता के बाद, भारत में जेल सुधार से सम्बंधित हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q.68) Consider the following statements related to National Health Policy 2017:

1. It aims to increase the government's expenditure on health to 2.5% of the GDP by 2025.
2. The policy advocates allocating major proportion of resources to primary care, followed by secondary and tertiary care.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.69) With which among the following is the "EK Duniya anEK Awaaz" associated with?

(a) Initiative of Ministry of Overseas Affairs to connect all Indians.
(b) Initiative of Ministry of Information and Broad Casting for connecting community radio stations across South Asia.
(c) Scheme of Ministry of Home Affairs to reach out to the Tribals in the Naxal Affected areas.
(d) Scheme of Ministry of Minority Affairs to connect all the Buddhists.

Q.70) The "ASIAN PREMIUM", which was in news recently, deals with

(a) Additional cost incurred by the Asian countries to counter climate change.
(b) Additional cost being collected by Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) from Asian countries when selling oil.
(c) Provision of additional quota in the International Monetary Fund (IMF) to India and China.
(d) Additional privileges given by World Trade Organisation (WTO) to the Asian Countries.

Q.71) Regarding the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, which of the following statements is/are correct?

1. High courts of respective states have been mandated to monitor the setting up of POCSO special courts for speedy trail.
2. The Act provides a penalty of six months for false reporting.
3. Only a male can be tried and punished under the Act.

Select the correct answer using code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.72) With reference to the Prison Reforms in India, which of the following statements are correct?

1. The modernisation and reform of prison system in India was started by T. B Macaulay.
2. 'Prisons' is a concurrent list subject under List III of the seventh schedule of the Indian Constitution.
3. Justice Mulla and Justice Krishna Iyer Committees are associated with Prison Reform in India, post-independence.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.73) "**जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) विधेयक**, 2017" [The Representation of People's Act (Amendment) Bill, 2017) **के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं**?

1. **इस विधेयक का उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों** (The Non-Resident Indians – NRIs) **को पहली बार मतदान का अधिकार प्रदान करना है।**
2. **यदि कोई "निवासी भारतीय नागरिक" अपने चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं है, तो यह विधेयक उसे प्रॉक्सी** (Proxy) **वोट देने का विकल्प प्रदान करता है।**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) **केवल** 1
(b) **केवल** 2
(c) 1 **और** 2 **दोनों**
(d) **न तो** 1, **न ही** 2

Q.74) "**ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडैक्स**, 2018" (The Global Liveability Index. 2018) **के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं**?

1. **यह इंडैक्स "इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट"** (The Economist Intelligence Unit) **के द्वारा, वार्षिक रूप से, प्रकाशित किया जाता है।**
2. **यह विश्व के शहरों को सुरक्षा और अपराधों की घटनाओं के मानदंडों के आधार पर स्थानक्रम (रैंक) प्रदान करता है।**
3. **भारत में रहने के लिए पुणे को सबसे अच्छे शहर की रैंक दी गई थी।**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) **केवल** 1
(b) **केवल** 1 **और** 3
(c) **केवल** 2 **और** 3
(d) 1, 2 **और** 3

Q.75) "**सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) अधिनियम**, 2017" [The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017] **के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं**?

1. **इस अधिनियम के तहत संगृहीत सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग गैर-सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।**
2. **यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है।**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) **केवल** 1
(b) **केवल** 2
(c) 1 **और** 2 **दोनों**
(d) **न तो** 1, **न ही** 2

Q.73) With reference to Representation of peoples Act (Amendment) Bill, 2017, which of the following statements is /are correct?

1. The Bill aims to provide Non Resident Indians with voting rights for the first time.
2. The Bill provides a Resident Indian citizen with the option to cast a proxy vote if he is not present in his electoral constituency.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q.74) With reference to Global Liveability Index, 2018, which of the following statements is/are correct?

1. It is published annually by the Economist Intelligence Unit.
2. It ranks the world cities on the parameter of safety and incidence of crimes.
3. Pune was ranked the best city in to live in India.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

Q.75) With reference to Collection of Statistics (amendment) Act, 2017, which of the following statements is /are **incorrect?**

1. The statistical data collected under this Act can be used for non-statistical purposes as well.
2. The Act is applicable to the state of Jammu and Kashmir.

Select the correct answer using code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

https://t.me/RausIAS https://t.me/RausIAS

FOUNDATION + CURRENT AFFAIRS

GENERAL STUDIES (PAPER –I)

FOUNDATION TEST –II

Test Code

FC19E1002

SUBJECT: NCERT Polity Class XI-XII + Current Affairs

Time Allowed: 1½ Hours **Maximum Marks: 150**

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES NOT HAVE ANY UNPRINTED OR TORN or MISSING PAGES OR ITEMS, ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
2. This Test Booklet contains **75** items (questions). Each item is printed both in **Hindi** and **English.** Each item comprises four responses (answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose ***ONLY ONE*** response for each item.
3. You have to mark all your responses ***ONLY*** on the separate Answer Sheet (OMR sheet) provided. Read the directions in the Answer Sheet.
4. ***All*** items carry equal marks.
5. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the response to various items in the Test booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions contained therein.
6. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator ***only the Answer Sheet.*** You are permitted to take away with you the Test Booklet.
7. **Penalty for wrong answers**:

   THERE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

   (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one-third** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

   (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a **wrong answer** even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.

   (iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.

ANSWERS & EXPLANATION OF NCERT POLITY CLASS XI-XII + CURRENT AFFAIRS

Q.1) (b)

स्पष्टीकरणः

- स्थानीय सरकार के प्रावधानों को 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था।
- ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान करती है।
- बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है।
- दसवीं अनुसूची "दल-बदल रोधी कानून" (The Anti-Defection Law) का प्रावधान करती है।
- इसे 52वें संविधान संशोधन, 1985, के द्वारा जोड़ा गया था।

Q.2) (c)

स्पष्टीकरणः

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) (a) सभी नागरिकों के लिए "वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" की गारंटी देता है।
- तथापि, यह स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों के अधीन है [अनुच्छेद-19(2)]
- ये हैं: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सभ्यता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित, मानहानि अथवा अपराध के लिए भड़काना।
- अतः, हमारे लोकतांत्रिक समाज में "अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता" की गुंज़ाइश नहीं है।

Q.3) (a)

स्पष्टीकरणः

- 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जारी किये गए प्रस्ताव में स्थानीय सरकार के प्रावधान शामिल थे।
- प्रस्ताव के कुछ प्रावधान निम्नलिखित थे:

स्थानीय निकायों में अधिकतर गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्य और अध्यक्ष होंगे।

(ii) स्थानीय निकायों पर राज्य का नियंत्रण प्रत्यक्ष के स्थान पर अप्रत्यक्ष होना चाहिए।

(iii) इन निकायों को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ संपन्न किया जाना चाहिए।

(iv) स्थानीय सरकारी कर्मियों को स्थानीय निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत संचालित किया जाना चाहिए।

Q.4) (d)

स्पष्टीकरणः

भारत की स्वतन्त्रता का अर्थ पूरे भारत की स्वतन्त्रता होना चाहिए ... स्वतंत्रता निचले स्तर से शुरू होनी चाहिए। इस प्रकार हर गांव एक गणतंत्र होगा ... इसलिए प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों के प्रबंधन में सक्षम होना चाहिए। असंख्य गांवों से बनी इस संरचना में, कभी-कभी फैलते हुए, कभी-कभी बढ़ते हुए मंडल होंगे। जीवन शीर्ष के द्वारा अनवरत एक पिरामिड होगा" - महात्मा गांधी

Q.5) (d)

स्पष्टीकरणः

- यह महसूस किया जाता है, कि पंचायतों सहित, स्थानीय सरकार के विषय को संविधान में पर्याप्त महत्व नहीं मिला था।
- इसके कुछ कारण यहां प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

(i) सर्वप्रथम, विभाजन के कारण हुई उथल-पुथल के परिणामस्वरूप संविधान में एकत्व की ओर झुकाव में वृद्धि हुई थी। नेहरू ने, स्वयं, चरम स्थानीयता को एकता और राष्ट्र के एकीकरण के लिए एक खतरे के रूप में देखा था।

(ii) दूसरा, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अगुआई में, संविधान सभा में एक शक्तिशाली आवाज उठी थी, जिसने यह महसूस किया, कि ग्रामीण समाज की गुटवाद और जातिवाद के आधार पर चलने वाली प्रकृति, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार के एक महान उद्देश्य को पराजित कर देगी।

(iii) संविधान सभा के कई सदस्य चाहते यह थे, कि गांव पंचायत भारत में लोकतंत्र का आधार हो, लेकिन वे गुटवाद और गांवों में मौजूद कई अन्य बुराईयों को लेकर चिंतित थे।

Q.6) (a)

स्पष्टीकरणः

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने 15 अलग-अलग रिपोर्टें प्रदान की है।

- इसकी छठी रिपोर्ट "स्थानीय शासन"पर है।

Q.7) (c)

स्पष्टीकरणः

- संशोधन ने अनिवार्य रूप से ग्राम सभा के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया था।
- ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के, मतदाताओं के रूप में पंजीकृत, सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे।
- ग्राम सभा की भूमिका एवं उसके कार्य राज्य विधानसभा के द्वारा तय किए जाते हैं।
- प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।

Q.8) (c)

स्पष्टीकरणः

- राज्य सरकार का विघटन, राज्य में सभी पंचायतों को स्वतः भंग नहीं करता है।
- प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
- यदि राज्य सरकार पंचायत की अपनी पांच साल की अवधि पूर्ण होने से पहले उसे (पंचायत को) भंग कर देती है, तो इस प्रकार के विघटन के छह महीने के अंदर-अंदर नए चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए।
- यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।
- 73वें संविधान संशोधन से पहले, कई राज्यों में, जिला निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते थे।
- इसके अतिरिक्त, विघटन के बाद तत्काल चुनावों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं था।

Q.9) (d)

स्पष्टीकरणः

- सभी पंचायत संस्थानों में एक-तिहाई पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, प्रदान किया जाता है।
- यदि राज्यों को आवश्यक लगता है, तो वे अन्य पिछड़े वर्गों (The Other Backward Classes - OBC) के लिए भी आरक्षण प्रदान कर सकते हैं।

Q.10) (d)

स्पष्टीकरणः

- भारत की जनगणना, 2011 की शहरी क्षेत्र की परिभाषा निम्नानुसार है:

1. वे सभी स्थान जिनमें नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित शहर क्षेत्र समिति हो।
2. अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों:

(i) न्यूनतम 5000 की जनसँख्या;

(ii) कार्यरत पुरुष जनसँख्या का कम से कम 75 प्रतिशत गैर-कृषि व्यवसायों में कार्यरत हो ; और

(iii) कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसँख्या घनत्व।

- शहरी इकाइयों की पहली श्रेणी को "सांविधिक शहर" (Statutory Towns) के रूप में जाना जाता है।
- इन शहरों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा कानून के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, 31 दिसंबर 2009 की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बावजूद, इनमें नगर निगम, नगर पालिका आदि जैसे स्थानीय निकाय होतें हैं।
- शहर की दूसरी श्रेणी को "जनगणना शहरों" (Census Towns) के रूप में जाना जाता है।
- ये जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर पहचाने गए थे।

Q.11) (a)

स्पष्टीकरणः

- कथन 2 और 4 गलत हैं।
- कथन-2 - इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है (लेकिन अल्पसंख्यक धर्म- ईसाईओं, मुस्लिमों, जैन, पारसियों, सिखों और बौद्ध के द्वारा प्रतिनिधित्व धर्मों की नहीं)।
- कथन-4- वित्तीय सहायता के लिए निर्भरता स्थानीय सरकारों की एक प्रमुख कमी है।
- "द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग" ने स्थानीय सरकार पर अपनी रिपोर्ट में कहा है, कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता में सुधार करने के लिए उपाय करने चाहिए।
- स्थानीय निकायों के पास, अपना स्वयं का, बहुत कम धन होता है।

- वित्तीय सहायता के लिए स्थानीय निकायों की राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भरता ने प्रभावी ढंग से काम करने की उनकी क्षमता को नष्ट कर दिया है।
- ग्रामीण स्थानीय निकाय एकत्रित कुल राजस्व का 0.24% प्राप्त करते है, जबकि वे सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय के 4% भाग के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए उनका व्यय उनकी आय से बहुत अधिक होता है। इस कारण ये अनुदान देने वालों पर निर्भर रहते हैं।

Q.12) (c)

स्पष्टीकरणः

अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है।

Q.13) (d)

स्पष्टीकरणः

· "संविधान" मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय है, जिसके अनुसार एक राज्य गठित अथवा शासित किया जाता है।

· किसी भी समाज के सदस्यों के मध्य अधिकतम समन्वय के सृजन हेतु, बुनियादी नियमों का एक समुच्चय प्रदान करने के लिए, हमें एक संविधान की आवश्यकता होती है |

· ये बुनियादी नियम कानूनी रूप से लागू करने योग्य होने चाहिए।

· संविधान समाज में सत्ता के मूल आवंटन को निर्दिष्ट करता है।

· वह यह भी तय करता है, कि कानून का निर्माण कौन करेगा।

· भारतीय संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया है, कि अधिकांश मामलों में "संसद" कानूनों और नीतियों का निर्णय करेगी।

· स्वयं संसद को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया जायेगा।

Q.14) (b)

स्पष्टीकरणः

- संविधान को, आधिकारिक रूप से, कुछ मूल्यों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के मध्य सही संतुलन स्थापित करना चाहिए।
- साथ ही उसे, समयानुसार आवश्यकतो एवं परिस्थितियों के अनुकूलन के लिए पर्याप्त रूप से लचीला भी होना चाहिए।
- यदि कोई संविधान बहुत कठोर है, तो परिवर्तन के कारण उसके भंग होने की संभावना रहती है।
- दूसरी ओर, एक बहुत लचीला संविधान किसी प्रकार की सुरक्षा या भविष्य प्रदान नहीं कर सकता है।
- इसलिए, भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता के कारण इसे "जीवित दस्तावेज़" कहा जाता है।

Q.15) (d)

स्पष्टीकरणः

· "धर्म की स्वतंत्रता" में धर्म के प्रति आस्था, उसके पालन और प्रचार करने की स्वन्त्रन्ता शामिल है।

· इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है।

· इसका अर्थ है, कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का चयन कर सकता है या "किसी भी धर्म का पालन नहीं करना" चुन सकता है।

Q.16) (b)

स्पष्टीकरणः

"स्वाधीनता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" में "वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" शामिल है, जो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है, कि वे बिना किसी भय के अपने विचार और अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें।

Q.17) (b)

स्पष्टीकरणः

- न्यायालय विभिन्न प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकती हैं, जिन्हें रिट (Writs) के रूप में जाना जाता है:

(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): इसका अर्थ है, कि न्यायालय यह आदेश देती है, कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तार करने के आधार वैध या संतोषजनक नहीं हैं, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश भी दे सकती है।

(ii) परमादेश (Mandamus): यह रिट न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है, जब न्यायालय ने यह पाया हो, कि कोई विशेष कार्यालय धारक (अधिकारी) कानूनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है और इस प्रकार से वह किसी व्यक्ति के अधिकार पर उल्लंघन कर रहा है।

(iii) निषेध (Prohibition): यह रिट न्यायालय (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) के द्वारा निचले

न्यायालय को क्षेत्राधिकार के उल्लंघन (उसके न्यायक्षेत्र से बाहर) करने पर जारी की जाती है।

(iv) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto): यदि न्यायालय को यह जानकारी मिलती है, कि कोई व्यक्ति कार्यालय धारण कर रहा है (सम्हाल रहा है), लेकिन वह उस कार्यालय को धारण करने के योग्य नहीं है, तो उस कार्यालय धारक (अधिकारी) को अधिकार पृच्छा रिट जारी की जाती है और उसे कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने से रोका जाता है।

उत्प्रेषण (Certiorari): इस रिट के अंतर्गत, न्यायालय निचली न्यायालय या प्राधिकरण को किसी लंबित मामले को किसी उच्चतर न्यायालय अथवा प्राधिकरण को स्थानांतरित करने का आदेश देती है।

Q.18) (a)

स्पष्टीकरणः

· डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' को, (अर्थात "संवैधानिक उपचारों के अधिकार" को) "संविधान का हृदय एवं आत्मा" माना है।

· ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से, अधिकारों की बहाली के लिए, संपर्क करने का अधिकार देता है।

· सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को निर्देश दे सकते हैं।

Q.19) (d)

स्पष्टीकरणः

· अनुच्छेद-29 और अनुच्छेद-30 अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी देते हैं।

· अनुच्छेद-29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान इस प्रकार से करता है, कि नागरिकों को/नागरिकों के किसी भी वर्ग को, उनकी जो एक अलग/विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

· अनुच्छेद-29 के अनुसार धर्म, वंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

· अनुच्छेद-30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म के आधार पर हैं अथवा भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा।

Q.20) (c)

स्पष्टीकरणः

· "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत" (The Directive Principles of State Policy – DPSP) भारत में कानून और नीतियों को तैयार करते समय केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान में रखने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

· "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों" का मूल उद्देश्य नीति निर्माताओं के समक्ष सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को स्थापित करना है।

· "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत" देश के शासन के मूलतत्त्व हैं और कानून बनाते समय राज्य द्वारा इन पर कर्तव्य पूर्वक विचार करने की अपेक्षा की जाती है।

· तथापि, 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत" न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।

- संविधान (छियासीवाँ - 86 वाँ - संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 A डाला गया था।

- इसमें, 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, एक मौलिक अधिकार के रूप में, जिस प्रकार से, विधिवत, राज्य निर्धारित करें, प्रावधान है।

Q.21) (d)

स्पष्टीकरणः

· चुनाव "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली" की विशेषताएं:

- बड़े -बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया जाता है।

- संपूर्ण देश एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है।

- किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकते हैं।

- मतदाता पार्टी के लिए वोट देता है।

- प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मतों की संख्या के प्रतिशत के अनुपात के आधार पर विधायिका में सीटें मिलती है।

- बहुसंख्यक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतता है।

- उदाहरण: इज़राइल, नीदरलैंड्स

Q.22) (c)

स्पष्टीकरणः

- भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सांसदों का चुनाव "फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट" प्रणाली" पर आधारित नहीं है।
- भारत में स्थानीय निकायों के चुनाव "राज्य चुनाव आयोग" के द्वारा करवाए जाते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन उसके पास अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक शक्तियाँ नहीं होती हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दोनों चुनाव आयुक्तों के पास, एक सामूहिक निकाय के रूप में, चुनावों से सम्बन्धित, सभी निर्णयों को लेने के लिए समान शक्तियाँ होती हैं।

Q.23) (a)

स्पष्टीकरणः

- राष्ट्रपति को केवल संसद के द्वारा ही, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, पद से हटाया जा सकता है।
- इस प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- महाभियोग का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है।
- संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, संविधान के उल्लंघन पर, जब राष्ट्रपति का महाभियोग किया जाता है, तो आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा अधिमानित किया जायेगा।

Q.24) (b)

स्पष्टीकरणः

भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार जनता के सदन (लोक सभा) के (या राज्यों के मामले में विधानसभा के) सदस्यों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

Q.25) (c)

स्पष्टीकरणः

- संविधान में 52वें संशोधन के माध्यम से "दल-बदल रोधी कानून" शामिल किया गया था।
- इसके बाद, इसे 91वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया गया था।
- इसका प्रावधान संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत है।
- सदन का पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होता है।

Q.26) (a)

स्पष्टीकरणः

- राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियाँ ही होती हैं।
- राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है।
- वह इसमें केवल परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव दे सकती है।
- धन विधेयक में राज्यसभा के द्वारा सुझाए गए संशोधन, लोकसभा के द्वारा स्वीकार भी किये जा सकते हैं अथवा नहीं भी।
- इसके अलावा, राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर धन विधेयक पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा विधेयक को राज्यसभा में पारित माना जाता है।

Q.27) (c)

स्पष्टीकरणः

- राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है।
- संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है।
- 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है।
- इन नामित सदस्यों में, अनुभूत क्षमता तथा अद्वितीय योग्यता प्राप्त विद्वान, विधिवेत्ता, शिक्षाविद, इतिहासकार, वैज्ञानिक, कवि एवं साहित्यकार, अभियंता, अर्थशास्त्री, प्रशासक, कलाकार और समाज सेवक शामिल होते हैं।
- शेष 238 सदस्यों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
- संविधान ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की है। अतः, हम यह समझ सकतें हैं, कि 'सहकारी आंदोलन' नामांकन के लिए कोई क्षेत्र नहीं है।

Q.28) (c)

स्पष्टीकरणः

- किसी भी संघीय देश में, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच (आपस में) कानूनी विवाद उठते रहते हैं।

- भारत में, ऐसे मामलों के समाधान की शक्ति भारत की सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।
- इसे सर्वोच्च न्यायालय का "मूल क्षेत्राधिकार" कहा जाता है, क्योंकि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ऐसे मामलों की सुनवाई करने की शक्ति है।
- न तो उच्च न्यायालयों और न ही निचले स्तर की न्यायालयों के पास इस प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार है।
- संघीय संबंधों के मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय का "मूल क्षेत्राधिकार" इसे संघीय मामलों के संबंध में निर्णयकर्ता के रूप में स्थापित करता है।
- इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय भी कानून की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकते हैं।
- अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है, कि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है, तो इस प्रकार के कानून को असंवैधानिक और अपरिहार्य घोषित किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट (Writs) जारी करने का अधिकार है।

Q.29) (d)

स्पष्टीकरणः

- "न्यायिक स्वतंत्रता" की अवधारणा इस बात पर आधारित है, कि सरकार के अन्य अंगों, जैसे कार्यपालिका और विधायिका, को न्यायपालिका के कार्यकलापों को इस प्रकार से अवरोधित नहीं चाहिए, कि वह न्याय करने में असमर्थ हो जाए।
- सरकार के अन्य अंगों को न्यायपालिका के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- न्यायाधीशों को भय अथवा पक्षपात के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए।
- भारतीय संविधान ने कई उपायों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है, जैसे कि, न्यायधीशों का निश्चित कार्यकाल; न्यायपालिका की वित्तीय स्वतन्त्रता; न्यायालय की अवमानना होने पर दंड अधिरोपित करना; आदि।

Q.30) (c)

स्पष्टीकरणः

- प्रश्न में दिए गए दोनों ही कथन सही हैं।
- जनहित याचिका से सम्बन्धित अन्य जानकारी निम्नांकित है :
- भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास मुख्यतः "जनहित याचिका" अथवा "सामाजिक कार्यवाही याचिका" (Social Action Litigation - SAL) के माध्यम से हुआ है।
- कानून में, सामान्यतः, कोई भी व्यक्ति अदालत के पास तभी जा सकता है, अगर उसे व्यक्तिगत रूप से पीड़ित किया गया हो।
- अर्थात, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, या वह किसी विवाद में शामिल है, तो वह न्यायालय जा सकता है।
- वर्ष 1979 के आसपास इस अवधारणा में एक बदलाव आया था।
- 1979 में, न्यायालय ने पीड़ित व्यक्तियों की ओर से, किसी और व्यक्ति के द्वारा दायर किये गए मामले में सार्वजनिक हित के मुद्दे पर विचार करने की परंपरा शुरू की थी।
- चूंकि, ऐसे मामलों में सार्वजनिक हित का मुद्दा अन्तर्हित था/होता है, अतः ऐसे मामलों को "जनहित याचिका" कहा जाने लगा।

Q.31) (c)

स्पष्टीकरणः

- भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन की बुनियाद पर आधारित है।
- विधायी और कार्यकारी क्षेत्र में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को "न्यायिक सक्रियता" (Judicial Activism) के रूप में माना जा सकता है।
- कानून की संवैधानिकता पर सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना "न्यायिक समीक्षा" (Judicial Review) का एक उदाहरण है, न कि "न्यायिक सक्रियता" (Judicial Activism) का।

Q.32) (d)

स्पष्टीकरणः

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान है:

(i) संघ सूची;

(ii) राज्य सूची; और

(iii) समवर्ती सूची

· अवशिष्ट शक्तियों में उन सभी मामलों को शामिल किया गया है, जिनका उपरोक्त 3 सूचियों में से किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया है।

· ऐसे मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है।

Q.33) (d)

स्पष्टीकरणः

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शर्त लगाना तथा जुआ खेलना, स्वास्थ्य और पुलिस राज्य सूची के भाग हैं।

Q34) (d)

स्पष्टीकरणः

· संविधान के निर्माता मानते थे, कि भारत को एक ऐसे संघीय संविधान की आवश्यकता है, जिसमें विविधतों को समायोजित किया जा सके।

· तथापि, संविधान निर्माताओं को भारत की एकता और अखंडता की भी चिंता थी, जिसके बारे में, उनका ऐसा विचार था, कि उन्हें (एकता और अखंडता को) केवल एक मजबूत केंद्र के द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता था।

· देश की एकता की चिंता के अतिरिक्त, संविधान के निर्माताओं को यह चिंता भी थी, कि देश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान एक मजबूत केंद्र सरकार के द्वारा, राज्यों की सरकारों के सहयोग से, किया जाना चाहिए।

· निर्धनता, निरक्षरता और संपत्ति की असमानता, ये कुछ ऐसी समस्याऐं थीं, जिन्हें नियोजन और समन्वय की आवश्यकता थी।

· एक मजबूत केंद्र सरकार बनाने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान:

(i) आपातकाल की घोषणा

(ii) नए राज्य का गठन

(iii) केंद्र के द्वारा राज्य के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति

(iv) राज्यपाल का कार्यालय, आदि

Q.35) (c)

स्पष्टीकरणः

• भारत जब "भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947" (The Indian Independence Act, 1947) के द्वारा स्वतंत्र हुआ, तब रियासतों (Princely States) के समक्ष तीन विकल्प थे:

- पहला, भारत में शामिल होना;
- दूसरा, पाकिस्तान में शामिल होना; और
- तीसरा, स्वतंत्र होना/रहना।

• जूनागढ़ का शासक मुस्लिम था और वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था।

• तथापि, जूनागढ़ की अधिकांश जनसँख्या हिंदूओं की थी।

• जनमत के माध्यम से इसका विलय भारत में किया गया था।

• हैदराबाद के लिए सैन्य हस्तक्षेप का संकेत नाम (Code Name) "पुलिस कार्रवाई" (Police Action) था।

• 11 अगस्त 1947 को मणिपुर के महाराजा बुद्धचंद्र ने भारत में शामिल होने के समझौते (The Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए थे।

Q.36) (c)

स्पष्टीकरणः

• भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात, "राज्य पुनर्गठन आयोग" (The State Reorganisation Commission) की स्थापना की गई और उसने भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना का सुझाव दिया था।

• आंध्र प्रदेश, मद्रास से निर्मित होने वाला पहला राज्य था, जो "राज्य पुनर्गठन आयोग" की सिफारिश पर आधारित था।

Q.37) (b)

स्पष्टीकरणः

• डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने "इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी" (The Independent Labour Party) एवं "अनुसूचित जाति संघ" (The Scheduled Caste Federation) की स्थापना की थी।

• ए.के. गोपालन "कम्युनिस्ट पार्टी" के एक अनुभवी नेता थे।

• सोशलिस्ट पार्टी पहले कांग्रेस पार्टी के गुट में थी, लेकिन बाद में (1948 में) यह उससे अलग हो गई थी।

• आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे।

Q.38) (d)

स्पष्टीकरणः

- ए. के. गोपालन, एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे और वे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया) के नेता के रूप में कार्यरत थे।
- लेकिन वे संविधान सभा के भाग/सदस्य नहीं थे।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के संविधान के मसौदे के लिए गठित संविधान सभा में कार्य किया था।
- वे 1952 में और फिर पुनः 1957 में लोकसभा के लिए चुने गए थे।
- राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी।
- वे एक प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी।
- राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की सदस्य थी।
- सी. राजगोपालाचारी मद्रास से संविधान सभा के लिए चुने गए थे।
- वे "अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति और उप-समिति" (The Advisory Committee and Sub-Committee on Minorities) के सदस्य थे।

Q.39) (d)

स्पष्टीकरणः

- योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं था।
- इसे 1950 में सरकार के एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- पहली पंच वर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी।
- यह मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी।
- यह, कुछ संशोधनों के साथ, "हैरोड-डोमर मॉडल" (The Harrod-Domar Model) पर आधारित थी।
- दूसरी पंच वर्षीय योजना, विशेष रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और "तीव्र औद्योगिकीकरण" पर आधारित थी।
- इस योजना में आर्थिक विकास के "महालनोबिस मॉडल" (The Mahalanobis Model) का अनुसरण किया गया था।

Q.40) (b)

स्पष्टीकरणः

- शिमला समझौते पर, 1972 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे।
- इसका उद्देश्य एक शांति संधि के अतिरिक्त, उससे कहीं अधिक, 1971 के युद्ध के परिणामों का उत्क्रम था।
- सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुए ताशकंद समझौते पर, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
- पहले बड़े पैमाने पर हुए एशियाई-अफ्रीकी अथवा एफ्रो-एशियाई सम्मेलन को "बांडुंग सम्मेलन" भी कहा जाता है।
- यह एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों की एक बैठक थी, जिनमें अधिकतर नव-स्वतंत्र राष्ट्र थे।
- यह 18-24 अप्रैल, 1955 को इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित हुई थी।

Q.41) (c)

स्पष्टीकरणः

- लोक लेखा समिति संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट स्वयं ही प्रस्तुत करती है।
- लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और यह पहली बार 1921 में गठित की गई थी।
- इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं तथा राज्यसभा के 7 सदस्य इससे सम्बन्धित होते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष को समिति के सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियमन खातों की और फिर उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है।

Q.42) (d)

स्पष्टीकरणः

- दिल्ली और पुडुचेरी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
- सांसदों / विधायकों के चुनाव से संबंधित विवादों के सभी निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा लिये जाते हैं।
- इनके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होता है।

· संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होतें हैं ।

Q.43) (a)

स्पष्टीकरणः

मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत - भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (The Indian Councils Act, 1909).

Q.44) (d)

स्पष्टीकरणः

- अनुच्छेद-45: राज्य सभी बच्चों के लिए, छह वर्ष की आयु पूरी होने तक. प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची शिक्षा (शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित) का वहन करती है।
- यह अनुसूची स्थानीय निकायों से संबंधित है।
- सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं:

(i) संघ सूची;

(ii) राज्य सूची; तथा

(iii) समवर्ती सूची

- सातवीं अनुसूची में "शिक्षा" से संबंधित प्रावधान हैं।
- शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है।
- भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में शिक्षा से सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है।

Q.45) (a)

स्पष्टीकरणः

राज्यसभा के पास यह शक्ति है, कि वह किसी धन विधेयक में संशोधन का सुझाव दे सकती है, किन्तु यह विवेकाधिकार सम्पूर्ण रूप से लोकसभा का है, कि वह संशोधन के इस सुझाव को स्वीकार करे अथवा नहीं।

Q.46) (b)

स्पष्टीकरणः

· प्रस्तावना के अंश:

- हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय;
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें, - व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता

· अनुच्छेद 38 : राज्य ऐसी व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

Q.47) (c)

स्पष्टीकरणः

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शासनात्मक सत्ता को यह मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, कि शासन कैसे किया जाये।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत उन सिद्धांतों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें नीतियों को तैयार करते समय राज्य के द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- ये हमारे संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद-36 से अनुच्छेद-51 तक सूचीबद्ध हैं।

Q.48) (c)

स्पष्टीकरणः

- अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, अर्थात, लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटा सकती है।
- भारतीय संविधान में "अविश्वास प्रस्ताव" का कोई उल्लेख नहीं है।
- राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को नहीं हटा सकती है।
- इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

Q.49) (b)

स्पष्टीकरणः

- प्राक्लन समिति 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति है, जिसके लिए प्रति वर्ष संसद के निचले सदन (लोकसभा) से सदस्यों का चयन, उसके सदस्यों में से, किया जाता है।

- सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति में संसद के दोनों सदनों से कुल 22 सदस्य (लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7) लिए जाते हैं।
- लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं।

Q.50) (b)

स्पष्टीकरणः

भारत की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है।

Q.51) (c)

स्पष्टीकरणः

- मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 की प्रमुख विशेषताएं:
- यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक मान्य सदस्य के रूप में "बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग" को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखता है |
- यह आयोग की संरचना में एक महिला सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखता है |
- यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पात्रता के दायरे में तथा चयन के दायरे में विस्तार करने का प्रस्ताव रखता है |
- यह केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए एक तंत्र को समाविष्ट करने का प्रस्ताव रखता है।
- यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की कार्यालय की अवधि में संशोधन करने का प्रस्ताव रखता है, ताकि उनका अन्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की कार्यालय की अवधि के साथ तालमेल बन सके।
- लाभ:
- ये संशोधन भारत के मानवाधिकार संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगें, ताकि वे अपने जनादेश, क्षेत्राधिकारों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का और अधिक प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।
- इसके अलावा, संशोधित अधिनियम, देश में लोगों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, वैश्विक मानकों और मानदंडों के अनुरूप होंगें।

Q.52) (d)

स्पष्टीकरणः

- इसका उद्देश्य, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें वे अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से वास्तविक बना सकें/ प्राप्त कर सकें।
- इसके अन्य लक्ष्य हैं: घटते हुए बाल लिंग अनुपात में सुधार करना; कन्या शिशु की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना; उसकी शिक्षा सुनिश्चित करना; और उसे अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना।
- इस कार्यक्रम के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
- इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों /केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जायेगा, जिसमें कुल लागत/व्यय की भागीदारी का अनुपात इस प्रकार से होगा:

(i) केंद्र: राज्य (अन्य/सामान्य श्रेणी वाले राज्य) - 60:40

(ii) केंद्र: राज्य (उत्तर-पूर्वी राज्य और विशेष श्रेणी वाले राज्य) - 90:10

Q.53) (b)

स्पष्टीकरणः

- स्वाधार गृह योजना का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों की पीड़ित उन महिलाओं की सहायता करना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता है, ताकि वे गरिमा के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर सकें।
- इस योजना में पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य के अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृहों की स्थापना की जाएगी।
- पीड़ित महिलाओं में, प्राकृतिक आपदाओं से जीवित बची हुई, जेल से रिहा की गई कैदी, घरेलू हिंसा की पीड़ित और मानव तस्करी पीड़ित महिलाओं / लड़कियों को शामिल किया गया है।
- यह योजना प्राथमिक रूप से महिलाओं के जीवन में गरिमा बहाल करने पर केंद्रित है।

Q.54) (b)

स्पष्टीकरणः

- यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा, विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से जारी की गई है।
- इस रिपोर्ट में राज्यों ओर केन्द्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के लिए तीन श्रेणियों में रखा गया है, ताकि एक समान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच आसानी से तुलना की जा सके।
- ये श्रेणियाँ हैं:

(i) बड़े राज्य ;

(ii) छोटे राज्य ; तथा

(iii) केन्द्र शासित प्रदेश

- यह स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र सूचकांक है, जो बड़े राज्यों के लिए तीन विभिन्न क्षेत्रों में संकेतकों पर आधारित है:

(i) स्वास्थ्य परिणाम (70 प्रतिशत);

(ii) शासन और सूचना (12 प्रतिशत); और

(iii) प्रमुख आगत और प्रक्रियाऐं (18 प्रतिशत)

- इसमें प्रत्येक श्रेणी का निर्धारण उसके महत्व के आधार पर किया गया है।
- रिपोर्ट में बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में केरल,पंजाब और तमिलनाडु को शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि वार्षिक स्तर पर प्रगति के मामले में झारखंड, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को शीर्ष तीन स्थान मिले हैं।
- छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में मिज़ोरम को पहला स्थान मिला है, जबकि मणिपुर दूसरे स्थान पर है।
- छोटे राज्यों में वार्षिक स्तर पर प्रगति के मामले में मणिपुर को प्रथम और गोवा को दूसरा स्थान दिया गया है।
- केन्द्र शासित प्रदेशों में, समग्र प्रदर्शन एवं वार्षिक स्तर पर प्रगति, दोनों ही क्षेत्रों में, लक्षद्वीप को शीर्ष स्थान मिला है।

Q.55) (a)

स्पष्टीकरणः

· इस मंच के सदस्यों में निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव सम्मिलित होंगें:

· सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; रेलवे; ऊर्जा; जल संसाधन; नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प; नवीन एवं अक्ष्य ऊर्जा; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; मानव संसाधन विकास; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन।

· इस मंच के सदस्यों में निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव भी सम्मिलित होंगें:

· असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम।

· इस नवगठित मंच की पहली बैठक अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित की गई थी।

Q.56) (a)

स्पष्टीकरणः

· "UPaAI" (Unified Planning and Analysis Interface) एप या "Solution" नामक यह एप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचना और सामाजिक सूचकांक के डेटा के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा।

· इसके साथ ही, यह एप लगभग 50 केंद्रीय योजनाओं और "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष" (The MP Local Area Development – MPLAD – Fund) पर जानकारी भी प्रदान करेगा।

· इस एप को गैर-लाभकारी "स्वनीति पहल" (Swaniti Initiative) और "अंक आहा' (Ank Aha) के द्वारा विकसित किया जा रहा है।

· प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।

Q.57) (d)

स्पष्टीकरणः

- मुख्य न्यायाधीश के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श लिया जाता है। [जैसा कि अनुच्छेद-124(2) में उल्लिखित है]
- अनुच्छेद-124 (3) (c) के अनुसार राष्ट्रपति किसी प्रतिष्ठित न्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और पुष्टि की विधि तीसरी अनुसूची में प्रदान की गई है।

Q.58) (c)

स्पष्टीकरणः

- "भारत की गुणवत्ता परिषद" वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (The Ministry of Commerce and Industry) के तत्वावधान के अधीन आती है।

- इस परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय मान्यता संरचना की स्थापना तथा संचालन हेतु, एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के द्वारा गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार और तीन प्रमुख उद्योग संघों के प्रतिनिधित्व में भारतीय उद्योगों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
- ये उद्योग संघ हैं:
- एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India - ASSOCHAM)
- कन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (The Confederation of Indian Industry - CII)
- फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry - FICCI)
- "भारत की गुणवत्ता परिषद" राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा ऐसे अन्य सभी क्षेत्रों में, जिनकी संगठित कार्यवाहियों/कार्यप्रणालियों का भारतीय नागरिकों की जीवन शैली की गुणवत्ता पर और उनके कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ऐसे सभी क्षेत्रों के प्रचार में, उन्हें अपनाने के लिए और उनका पालन करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती है।
- ये क्षेत्र हैं :
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, अभिशासन, सामाजिक क्षेत्र, आधारिक संरचना क्षेत्र, इत्यादि।

Q.59) (a)

स्पष्टीकरणः

- "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार अथवा निजी एजेंसियों (केवल निजी एजेंसियों द्वारा नहीं) के द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करती है तथा ऐसी मान्यता प्रदान के लिए शर्तों का निर्धारण करती है।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना 1956 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। (तत्कालीन राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार में प्रक्षिशण परिषद)।
- उक्त परिषद को निम्नलिखित दायित्व सौंपें गए हैं:

(i) शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए मानकों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना;

(ii) समग्र नीति और कार्यक्रमों पर भारत सरकार को सलाह देना;

(iii) अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा आयोजित करना; और

(iv) राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

Q.60) (b)

स्पष्टीकरणः

- अनुच्छेद - 90 में उपाध्यक्ष के कार्यालय से अवकाश और त्यागपत्र, और हटाने के बारे में उल्लेख किया गया है।
- अनुच्छेद 90 (a) के अनुसार - राज्यों की परिषद के उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला सदस्य, यदि परिषद का सदस्य नहीं रहता है, तो उसे अपने पद को छोड़ना होगा।
- राज्यसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है।
- उपाध्यक्ष को उसके कार्यालय/पद से हटाने के लिए, पहले इस आशय का एक प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है, फिर उसके चौदह दिन के नोटिस के बाद, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से वह प्रस्ताव पारित किया जाता है।

Q.61) (b)

स्पष्टीकरणः

- "2022 तक डिजिटल नॉर्थ ईस्ट" के लिए "विज़न दस्तावेज़" क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और बीपीओ (BPO) की संख्या को दोगुनी करके लोगों के जीवन में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।
- विज़न दस्तावेज उत्तर पूर्व के लोगों के जीवन को बदलने और जीवन जीने की सुगमता में वृद्धि करने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर जोर देता है।
- तथापि, यह दस्तावेज़ पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित नहीं है।
- "असम समझौते" के प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने के लिए असम के निवासियों के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अनिवार्य कर दिया गया है।

Q.62) (b)

स्पष्टीकरणः

- "बॉम्बे भिक्षावृति रोकथाम अधिनियम, 1959" (The Bombay Prevention of Begging Act, 1959), जो दिल्ली के केंद्रशासित प्रदेश में भी लागू है, भिक्षावृति को अपराध मानता है।
- तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, अपने हाल ही के एक निर्णय में, भीख मांगने की क्रिया का वि-अपराधीकरण कर दिया है और यह माना है, कि "भिक्षा अधिनियम, 1959" भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (कानून से समक्ष समानता) और अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Q.63) (d)

स्पष्टीकरणः

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन शुरू किया था।
- इस अभियान का उद्देश्य है: ऐसे सतत और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना, जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएँ और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन तथा एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करे, एवं "स्मार्ट" समाधानों के प्रयोग का मौका दें।
- इस अभियान का विशेष ध्यान सतत और समावेशी विकास पर है।
- इनके अतिरिक्त, इसका विचार एक ऐसा अनुकरणीय मॉडल बनाने का है, जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है, जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सके, तथा विभिन्न क्षेत्रों और देश के भागों में भी इसी तरह के स्मार्ट सिटी के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके।
- इस प्रकार से किया गया व्यापक विकास जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, रोज़गारों का सृजन करेगा और सभी लोगों की, विशेषरूप से निर्धनों एवं वंचित लोगों की, आमदनी में वृद्धि करेगा, तथा इस प्रकार से समावेशी शहरों का निर्माण होगा ।

Q.64) (b)

स्पष्टीकरणः

- इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड, सुरक्षा से सम्बन्धित भौगोलिक मंच के लिए, एक (एकल) कमांडर के अधीन, तीन सेवाओं की एक एकीकृत कमांड की परिकल्पना करती है।
- इस तरह के बल का कमांडर भारतीय वायु सेना, थल सेना और नौसेना से, निर्बाध प्रभावकारिता के साथ, अपने संसाधनों को पूरा करने में सक्षम होगा।
- इंटीग्रेटेड थियेटर कमांडर व्यक्तिगत सेवाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- वह नामित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम, एक समेकित योद्धा बल बनाने के लिए अपनी कमांड को प्रशिक्षित करने, लैस करने और उसका अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- अपने अभियानों के संचालन के लिए आवश्यक रसद संसाधनों को थिएटर कमांडर के अधीन रखा जाएगा, ताकि अभियान शुरू होने पर उसे इधर-उधर न देखना पड़े।

Q.65) (c)

स्पष्टीकरणः

- कथन-2: अनुच्छेद-35 (A) को भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से, संविधान (जम्मू-कश्मीर के लिए विनियोग) आदेश, 1954 [The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954] के द्वारा जोड़ा गया था, ना कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन के द्वारा।
- कथन-4: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था, की संसद द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है, जिससे की संविधान का मूलभूत ढाँचा नष्ट हो जाये।
- संविधान के मूलभूत ढांचे से सम्बंधित कुछ विशेषताएं, जो असंशोधनीय हैं:
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - सरकार का गणतन्त्रोक्त एवं लोकतांत्रिक स्वरुप
  - संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
  - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन
  - संविधान का संघीय चरित्र
- न्यायालय ने यह भी कहा था, कि मूलभूत विशेषताओं की यह सूची एक विस्तृत सूची नहीं है तथा, यदि आवश्यक हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें नए तत्वों को जोड़ा जा सकता है।
- इस प्रकार, मिनर्वा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें तीन और मूलभूत विशेषताओं को जोड़ा गया था, यथा-

- विभिन्न मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से सुरक्षित की गई व्यक्ति की गरिमा
- राष्ट्र की एकता और अखंडता
- संसदीय प्रणाली

Q.66) (b)

स्पष्टीकरण:

- "इंद्रधनुष योजना" सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अभिशासन में व्यवस्थित परिवर्तन लाने पर केंद्रित है।
- इस योजना के 7 तत्व हैं:

(i) नियुक्तियाँ

(ii) बैंक बोर्ड ब्यूरो

(iii) पूंजीकरण

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तनाव को कम करना (गैर-निष्पादिक परिसंपत्तियों – NPAs - की समस्या का समाधान करना)

(v) सशक्तिकरण

(vi) उत्तरदायित्व का ढांचा

(vii) अभिशासन में सुधार

- इसके अतिरिक्त, हमें "मिशन इंद्रधनुष" (Mission Indradhanush) के बारे में भी पता होना चाहिए, जो "इंद्रधनुष योजना" (The Indradhanush Plan) से भिन्न है।
- मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य है: वर्ष 2020 तक 7 निवारणीय रोगों [डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक (टीबी), खसरा और हेपेटाइटिस बी] के टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों को, अथवा उन सभी बच्चों को कवर करना, जिन्हें आंशिक रूप से टीके लगे हैं।

Q.67) (b)

स्पष्टीकरण:

- "इंद्रधनुष योजना" सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अभिशासन में व्यवस्थित परिवर्तन लाने पर केंद्रित है।
- इस योजना के 7 तत्व हैं:

(i) नियुक्तियाँ

(ii) बैंक बोर्ड ब्यूरो

(iii) पूंजीकरण

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तनाव को कम करना (गैर-निष्पादिक परिसंपत्तियों – NPAs - की समस्या का समाधान करना)

(v) सशक्तिकरण

(vi) उत्तरदायित्व का ढांचा

(vii) अभिशासन में सुधार

- इसके अतिरिक्त, हमें "मिशन इंद्रधनुष" (Mission Indradhanush) के बारे में भी पता होना चाहिए, जो "इंद्रधनुष योजना" (The Indradhanush Plan) से भिन्न है।
- मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य है: वर्ष 2020 तक 7 निवारणीय रोगों [डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक (टीबी), खसरा और हेपेटाइटिस बी] के टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों को, अथवा उन सभी बच्चों को कवर करना, जिन्हें आंशिक रूप से टीके लगे हैं।

Q.68) (c)

स्पष्टीकरण:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण नीति, 2017 कल्याण की ओर अग्रसर होने के लिए एक व्यापक एकीकृत तरीके से सभी तक पहुंचने का प्रयास करती है।
- इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना और सस्ती लागत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है।
- यह नीति रणनीतिक भागीदारों के रूप में निजी क्षेत्र के साथ समग्र रूप से समस्याओं और समाधानों को देखती है।
- यह नीति देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है।
- यह उभरती हुई बीमारियों पर केंद्रित है, और यह प्रोत्साहक एवं निवारक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करती है।
- यह नीति स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बड़े पैकेज प्रदान करने की परिकल्पना करती है।
- यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज में बहुत ही चयनात्मक से लेकर व्यापक परिवर्तन को दर्शाती है।
- इसमें वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, प्रशामक देखभाल तथा पुनर्वास सम्बन्धित देखभाल सेवाएँ शामिल हैं।

Q.69) (b)

स्पष्टीकरण:

- "एक दुनिया अनेक आवाज" (EK duniya anEK awaaz - EDAA) - वन वर्ल्ड, मैनी वॉयसिज़ (One World Many Voices), दक्षिण एशिया में सामुदायिक रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए एक वेब आधारित निःशुल्क और मुक्त ऑडियो सामग्री और संसाधन विनिमय मंच है।
- इसका उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को पार करके, संसाधनों के सार्थक उपयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- यह "वन वर्ल्ड साउथ एशिया" (One World South Asia) के द्वारा संकल्पनाबद्ध एवं संचालित है।
- यह मंच भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा उत्प्रेरित, समन्वित और समर्थित है।
- "कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मिडिया सेंटर फॉर एशिया " (The Commonwealth Educational Media Centre for Asia – CEMCA) इसका रणनीतिक साझेदार है।

Q.70) (b)

स्पष्टीकरण:

- एशियाई प्रीमियम इस अवधारणा को संदर्भित करता है, कि एशियाई महाद्वीप के देशों को, ओपेक देशों से पेट्रोलियम के आयात पर, धनी पश्चिमी देशों की तुलना में, अधिक भुगतान करना पड़ता है।
- इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (The International Energy Forum – IEF) की बैठक में भारत सरकार यह मुद्दा उठाएगी।
- इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (The International Energy Forum – IEF) - "इंटरनेशनल एनर्जी फोरम" का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच सामान्य ऊर्जा हितों की अधिक पारस्परिक समझ और जागरूकता को बढ़ावा देना है।
- फोरम के 72 सदस्य देश "इंटरनेशनल एनर्जी फोरम चार्टर" (The International Energy Forum Charter) के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो इस अंतर-सरकारी व्यवस्था के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा वार्ता के ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है।
- यह सभी छह महाद्वीपों और तेल एवं गैस की 90% वैश्विक आपूर्ति कवर करने वाला एक अद्वितीय मंच है, जिसमें न केवल उपभोग करने वाले तथा उत्पादन करने वाले IEF के सदस्य देश और ओपेक देश शामिल हैं, बल्कि इसमें इनकी सदस्यता के बाहर के महत्वपूर्ण पारगमन देश, जैसे अर्जेंटीना, चीन, भारत, मैक्सिको, रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं।
- फोरम की द्विवार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक विश्व में ऊर्जा मंत्रियों की सबसे बड़ी सभा/ बैठक है।
- IEF और वैश्विक ऊर्जा वार्ता को रियाद, सऊदी अरब में स्थित अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के स्थायी सचिवालय के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।
- "ओपेक" (OPEC – The Organisation of Petroleum Exporting Countries) :
- "ओपेक" (OPEC – The Organisation of Petroleum Exporting Countries) की स्थापना सितम्बर, 1960 में, बगदाद, ईराक़ में, 5 देशों (ईरान इस्लामिक गणराज्य, ईराक़, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला) के द्वारा हस्ताक्षर से हुई थी
- ये 5 देश इस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं।
- ओपेक सचिवालय, ओपेक का कार्यकारी अंग है।
- यह विएना में स्थित है।
- यह इस संस्था के मुख्यालय का काम भी करता है।

Q.71) (b)

स्पष्टीकरण:

- राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना की निगरानी करना "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग" (The National Commission for Protection of Child Rights – NCPCR) का क्षेत्राधिकार है।
- पॉक्सो अधिनियम "बच्चे" को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।
- बलात्कार कानूनों के विपरीत, पॉक्सो लिंग तटस्थ है।
- इसलिए, इसके अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर लड़कों और लड़कियों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

Q.72) (b)

स्पष्टीकरण:

- भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – II, या "राज्य सूची" के अंतर्गत जेल एक राज्य विषय है।
- जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

Q.73) (d)

स्पष्टीकरण:

- "जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010" [The Representation of People's (Amendment) Act, 2010] में पहली बार अप्रवासी भारतीयों के लिए मतदान का प्रावधान किया गया था।
- लेकिन इस अधिनियम में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं दिया था।
- उन्हें चुनाव के समय अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्वयं उपस्थित होना आवश्यक था।
- 2017 का विधेयक एक ओवरसीज मतदाता/अप्रवासी भारतीय को व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देने के लिए के लिए "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951" (The Representation of People's Act, 1951) में संशोधन का प्रयास करता है।
- ऐसा अधिकार केवल एक अप्रवासी भारतीय के लिए ही उपलब्ध है, न कि एक "सामान्य निवासी भारतीय नागरिक" के लिए।
- विधेयक का उद्देश्य "पत्नी" शब्द को "पति/पत्नी" के साथ बदलकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अधिक लिंग तटस्थ बनाना भी है।

Q.74) (a)

स्पष्टीकरणः

- "इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट" एक वार्षिक "ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडैक्स रैंकिंग" प्रकाशित करता है, जो 140 शहरों के लिए शहरी जीवन गुणवत्ता के आधार पर स्थिरता, स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और आधारिक संरचना का आंकलन करता है।
- भारत के केवल 2 शहरों, दिल्ली और मुंबई, को इस वार्षिक सूचकांक में शामिल किया गया था।
- इसमें दिल्ली को 112 वा और मुंबई को 117 वा स्थान प्राप्त हुआ है।
- इसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान पर रखा गया है।

Q.75) (d)

स्पष्टीकरणः

- केंद्र सरकार उस तरीके को निर्धारित कर सकती है, जिसके द्वारा सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।
- अधिनियम के संशोधन ने इसे जम्मू और कश्मीर राज्य में भी विस्तृत कर दिया है।
- जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल ने "जम्मू और कश्मीर सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2010" (The Jammu and Kashmir Collection of Statistics Act, 2010) को अधिनियमित किया था, जो पूरे जम्मू और कश्मीर में लागू है और यह केंद्रीय कानून की लगभग प्रतिकृति है।
- "सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008" और "जम्मू और कश्मीर सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2010", संघ सूची में आने वाले सांख्यिकीय विषयों पर लागू नहीं होते थे, जैसा कि "संविधान (जम्मू और कश्मीर अनुप्रयोग) आदेश, 1954" [The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954] के तहत जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है।
- इसने एक विधायी निर्वात उत्पन्न कर दिया था।
- इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर में केंद्र के द्वारा उपयोग किए जाने वाले समवर्ती क्षेत्राधिकार को सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 में भी प्रदान नहीं किया गया था।
- संशोधन कानून ने उक्त निर्वात भर दिया है।

ANSWERS & EXPLANATION OF
NCERT Polity Class XI-XII + Current Affairs

Q.1) (b)

Explanation.

- The provisions of local government were added by the Constitution 73rd and 74th Amendment, 1992.
- Eleventh Schedule provides for Panchayats
- Twelfth Schedule provides for Municipalities.
- Tenth Schedule provides for 'Anti-Defection Law'. It was added by the Constitution 52th Amendment, 1985.

Q.2) (c)

Explanation –

- **Article 19(1)(a)** of the Constitution of India guarantees **freedom of speech and expression to all citizens**. However, this freedom is subjected to certain restrictions [Article 19(2)] namely, interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
- So, there is no scope of Absolute freedom of expression in our democratic society.

Q.3) **(a)**

Explanation –

- Resolution issued by Lord Ripon in 1882 contained the provisions for local government. Some of the provisions of resolutions were -
  - Local bodies should have mostly elected non-governmental members and chairman.
  - The state control over local bodies should be indirect rather than direct.
  - These bodies must be endowed with adequate financial resources to carry out their functions.
  - Local government personnel should be operated under the administrative control of the local bodies.

Q.4) (d)

Explanation –

- *The independence of India should mean the independence of the whole of India...Independence must begin at the bottom. Thus every village will be a republic... It follows therefore that every village has to be self-sustained and capable of managing its affairs. In this structure composed of innumerable villages, there will be ever-widening, ever-ascending circles. Life will be a pyramid with the apex sustained by the bottom* - ***Mahatma Gandhi***

Q.5) (d)

Explanation

- It is felt that the subject of local government including panchayats did not receive adequate importance in the Constitution. A few reasons can be advanced here.
  - **Firstly,** the turmoil due to the Partition resulted in a strong unitary inclination in the Constitution. Nehru himself looked upon extreme localism as a threat to unity and integration of the nation.
  - **Secondly,** there was a powerful voice in the Constituent Assembly led by Dr. B.R. Ambedkar which felt that the faction and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at the rural level
  - Many members of the Constituent Assembly wanted Village Panchayats to be the basis of democracy in India but they were concerned about

factionalism and many other ills present in the villages.

Q.6) (a)

- Second Administrative Reform Commission provides for 15 different reports. Its sixth Report is on Local Governance.

Q.7) (c)

Explanation –

- The amendment also made a provision for the mandatory creation of the Gram Sabha. The Gram Sabha would comprise **all the adult members registered as voters in the Panchayat area**. Its role and functions are decided by State legislation. The term of each Panchayat to be fixed at **five years.**

Q.8) (c)

Explanation –

- Dissolution of state government does not automatically dissolve all panchayats in the state. The term of each Panchayat body is five years. If the State government dissolves the Panchayat before the end of its five-year term, fresh elections must be held within six months of such dissolution. This is an important provision that ensures the existence of elected local bodies. Before the 73rd amendment, in many States, there used to be indirect elections to the district bodies and there was no provision for immediate elections after dissolution.

Q.9) (d)

Explanation –

- One third of the positions in all panchayat institutions are **reserved for women**. Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also provided for at all the three levels, in proportion to their population. If the States find it necessary, they can also provide for reservations for the other backward classes (OBCs).

Q.10) (d)

Explanation

- For the Census of India 2011, the definition of urban area is as follows;
  1. All places with a municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee, etc.
  2. All other places which satisfied the following criteria:
  - A minimum population of 5000;
  - At least 75 per cent of the male main working population engaged in non-agricultural pursuits; and
  - A density of population of at least 400 persons per sq. km.
- **The first category of urban units** is known as **Statutory Towns**. These towns are notified under law by the concerned State/UT Government and have local bodies like municipal corporations, municipalities, municipal committees, etc., irrespective of their demographic characteristics as reckoned on 31st December 2009. **The second category of Towns** (as in item 2 above) is known as **Census Town**. These were identified on the basis of Census 2001 data.

Q.11) (a)

Explanation

- Statement 2 and 4 are incorrect.
- **Statement 2 –** It led to increased representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class. (but not the minority religion represented through Christians, Muslims, Jains, Parsis, Sikh and Buddhists).
- **Statement 4-** Dependence of financial support is one of the **drawbacks of local self-government**. **Second Administrative Reform Commission** in its report on Local Governance has pointed out that centre and state governments must find ways to improve revenue generating capacity for panchayats and municipalities to make them self-sustaining.
- Local bodies have very little funds of their own. The dependence of local bodies on the central and state

governments for financial support has greatly eroded their capacity to operate effectively. While rural local bodies raise 0.24% of the total revenues collected, they account for 4% of the total expenditure made by the government. So, they earn much less than they spend. That makes them dependent on those who give them grants.

Q.12) (c)

Explanation:

- The idea of Residuary Powers has been borrowed from the Canadian Constitution.

Q.13) (d)

Explanation:

- A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed.
- We need a constitution to provide a set of basic rules that allow for coordination amongst members of a society which are legally enforceable. The constitution specifies the basic allocation of power in a society. It decides who gets to decide what the laws will be. In the Indian Constitution, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner.

Q.14) (b)

Explanation:

- A constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances.
- Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change; a constitution that is, on the other hand, too flexible, will give no security or predictability.
- Hence, due to this ability of the Indian constitution to strike a balance between Rigidity and Flexibility, it is referred to as "Living Document".

Q.15) (d)

Explanation:

- The 'Freedom of religion' includes the freedom to profess, follow and propagate any religion. It also includes the freedom of conscience. It means that a person may choose any religion or may choose not to follow any religion.

Q.16) (b)

Explanation:

- The Right to Liberty and Personal Freedom includes the Freedom of Speech and Expression which gives the Fundamental Right to all the citizens to express their views and opinions freely without any fear.

Q.17) (b)

Explanation:

- The courts can issue various special orders known as writs.
- Habeas corpus: Means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory.
- Mandamus: Issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual.
- Prohibition: Issued by a higher court (High Court or Supreme Court) when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction.
- Quo Warranto: If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder.
- Certiorari: Under this writ, the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court.

Q.18) (a)

Explanation:

- Dr. B. R. Ambedkar called 'Article 32' of the Indian Constitution i.e. Right to Constitutional remedies as 'the heart and soul of the Constitution'.
- Because this right gives a citizen the right to approach a High Court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation.
- The Supreme Court and the High Courts can issue orders and give directives to the government for the enforcement of rights.

Q.19) (d)

Explanation:

- Article 29 and Articles 30 guarantee certain right to the minorities. Article 29 protects the interests of the minorities by making a provision that any citizen / section of citizens having a distinct language, script or culture have the right to conserve the same. Article 29 mandates that no discrimination would be done on the ground of religion, race, caste, language or any of them.
- Article 30 mandates that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

Q.20) (c)

Explanation:

- Directive Principle of State Policy provides guidelines to central & state government in India to be kept in mind while framing laws & policies.
- The basic aim of DPSPs is to set up social & economic goals before the law makers.
- DPSPs are fundamentals in governance of the country & shall be considered dutifully by the state while making laws, however DPSPs are not enforceable in court of law.
- The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21 A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such a manner as the State may, by law, determine.

Q.21) (d)

Explanation:

- Features of Proportional Representation system of Election:
  - Large geographical areas are demarcated as constituencies. The entire country may be a single constituency.
  - More than one representative may be elected from one constituency
  - Voter votes for the party
  - Every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets
  - Candidate who wins the elections gets majority of votes.
  - **Examples:** Israel, Netherlands

Q.22) (c)

Explanation:

- The election of President, Vice President and Rajya Sabha MPs are not based on First Past the Post system (FPTP).
- The elections to the local bodies in India is conducted by the State Election Commission.
- The Chief Election Commissioner (CEC) presides over the Election Commission, but does not have more powers than the other two Election Commissioners. The CEC and the two Election Commissioners have equal powers to take all decisions relating to elections as a collective body.

Q.23) (a)

Explanation:

- The President can be removed from office only by Parliament by following the procedure of Impeachment. This procedure requires special majority. The only ground for impeachment is violation of the Constitution.
- According to Article 61 of the Constitution, when a President is to be

impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.

Q.24) (b)

Explanation:

- The 91st amendment to the Indian constitution states that the size of Council of Ministers shall not exceed 15 percent of total number of members of the House of People (or Assembly, in the case of the States).

Q.25) (c)

Explanation:

- Anti-defection was introduced through the 52nd Amendment Act, 1985 to the Constitution. It has also been subsequently modified by the 91st amendment. It is provided under the Tenth Schedule of the Constitution.
- The presiding officer of the House is the authority who takes the final decision on all such cases.

Q.26) (a)

Explanation:

- The Rajya Sabha has limited powers with respect to Money Bill. The Rajya Sabha cannot reject or amend the Money Bill. It can only suggest changes. Amendments to the bill, suggested by Rajya Sabha, may or may not be accepted by Lok Sabha.
- Further, the Rajya Sabha is required to act on the money bill within 14 days, else the bill is deemed to be passed.

Q.27) (c)

Explanation:

- The Rajya Sabha is an indirectly elected House. The Constitution fixed the maximum number of membership of the Rajya Sabha at 250. Out of 250 members 12 are nominated by the President. These nominated members include scholars, jurists, educationists, historians, scientists, poets and litterateurs, engineers, economists, administrators, artistes and social workers of proven ability and outstanding merit.
- The rest 238 members are to be elected by the State Legislative Assemblies of different States and Union Territories. The Constitution has fixed the number of elected representatives from each State. Therefore, we can understand that cooperative movement is not a field for nomination.

Q.28) (c)

Explanation:

- In any federal country, legal disputes are bound to arise between the Union and the States; and among the States themselves. The power to resolve such cases is entrusted to the Supreme Court of India. It is called original jurisdiction because the Supreme Court alone has the power to deal with such cases. Neither the High Courts nor the lower courts can deal with such cases.
- Cases involving federal relations go directly to the Supreme Court. The Original Jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an umpire in all disputes regarding federal matters.
- Further, both the Supreme Court as well as High Courts can examine the constitutionality of any law. If the Court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the Constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable.
- Both Supreme Court and High Court are empowered to issue writs in case of violation of Fundamental Rights.

Q.29) (d)

Explanation:

- The concept of "Judicial Independence" is based on the premise that the other organs of the government like the executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice.
- The other organs of the government should not interfere with the decision of the judiciary. Judges must be able to perform their functions without fear or favour.

- The Indian Constitution has ensured the independence of the judiciary through a number of measures like fixed tenure for the judges, financial independence on the executive or judiciary, imposing penalty over contempt of court etc.

Q.30) (c)

Explanation:

- Both statements are correct.
- Other information related to PIL are given below:

- The chief instrument through which judicial activism has flourished in India is Public Interest Litigation (PIL) or Social Action Litigation (SAL). In normal course of law, an individual can approach the courts only if he/she has been personally aggrieved.
- That is to say, a person whose rights have been violated, or who is involved in a dispute, could move the court of law. This concept underwent a change around 1979.
- In 1979, the Court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved persons but by others on their behalf. As this case involved a consideration of an issue of public interest, it and such other cases came to be known as public interest litigations.

Q.31) (c)

Explanation:

- The Indian Constitution is based on the bedrock of separation of powers between legislature, Executive and Judiciary. The Interference of the judiciary in the legislative and executive sphere can be considered as "Judicial Activism".
- The deliberation of the Supreme Court on the Constitutionality of law is considered to be Judicial Review and not activism.

Q.32) (d)

Explanation:

- The Seventh schedule of the Indian constitution provides for 3 lists- Union List, State list and Concurrent List. The residuary powers include all other matters which are not mentioned in any of the lists. The Parliament alone has the power to legislate on such matters.

Q.33) (d)

Explanation:

- Betting and gambling, Health and Police are part of state list under the Seventh Schedule of Indian Constitution.

Q.34) (d)

Explanation:

- The framers of the Constitution believed that we required a federal constitution that would accommodate diversities. However, the founding fathers had a concern related to unity and integrity of India, which they felt could be safeguarded only by Strong Centre.
- Besides the concern for unity, the makers of the Constitution also believed that the socio-economic problems of the country needed to be handled by a strong central government in cooperation with the States. Poverty, illiteracy and inequalities of wealth were some of the problems that required planning and coordination.
- The important provisions that create a strong central government:
  - Formation of new state
  - Declaration of Emergency
  - Office of Governor
  - Power of the centre to issue instructions to the state etc

Q.35) (c)

- When India became independent through India Independence Act of 1947, princely states had three options. First was to become part of India, second was to become part of Pakistan and third was to become Independent.
- Ruler of Junagarh was Muslim and wanted to become part of Pakistan. However, the population of Junagarh

was largely Hindu and it was merged with India through plebiscite. The "code name" of army intervention for Hyderabad was "Police Action". On 11 August 1947, Maharaja Budhachandra of Manipur signed the Instrument of Accession, joining India.

Q.36) (c)

- After India became independent, State reorganization commission was established and it suggested establishment of states on the basis of language. Andhra Pradesh was the first state to carved out of Madras which was based on the recommendation of state reorganization commission.

Q.37) (b)

- Dr B R Ambedkar founded the independent labour party and Scheduled Caste Federation.
- AK Gopalan was a veteran leader of the communist party.
- Socialist party was earlier a faction of congress party but later split in 1948.
- Acharya Narendra Dev was founding president of the Socialist party.

38) (d)

Explanation:

- A. K. Gopalan, was an Indian communist leader and served as the leader of the second largest party (CPI). But he was not part of constituent assembly.
- Maulana Abul Kalam Azad served in the Constituent Assembly formed to draft India's constitution and was elected to the Lok Sabha in 1952 and again 1957.
- Rajkumari Amrit Kaur was the first health minister of India, an eminent Gandhian, a freedom fighter, and a social activist.
- Rajkumari Amrit Kaur was also a member of the Constituent Assembly.
- C. Rajgopalchari was elected to the Constituent Assembly from Madras. He was a part of Advisory Committee and Sub-Committee on Minorities.

Q.39) (d)

- Planning commission was not a constitutional body, it was set up by a simple resolution of the government in 1950. The First Five-year Plan was launched in 1951 which mainly focused in development of the primary sector.
- The First Five-Year Plan was based on the Harrod–Domar model with few modifications. The Second Plan was particularly in the development of the public sector and "rapid Industrialisation". The plan followed the Mahalanobis model of economic development.

Q.40) (b)

- The Simla Agreement signed by Prime Minister Indira Gandhi and President Zulfikar Ali Bhutto of Pakistan in 1972 was much more than a peace treaty seeking to reverse the consequences of the 1971 war.
- Tashkent agreement, brokered by Soviet Union, was signed to end the 1965 India- Pakistan war.
- The first large-scale Asian–African or Afro–Asian Conference—also known as the Bandung Conference. It was a meeting of Asian and African states, most of which were newly independent, which took place on April 18–24, 1955 at Bandung, Indonesia.

Q.41) (c)

- Public Accounts Committee lays down report in parliament on its own.
- The Committee on Public Accounts is the oldest Parliamentary Committee and was first constituted in 1921. The Committee consists of 22 Members, 15 Members are elected by Lok Sabha and 7 Members of the Rajya Sabha are associated with it. The Speaker is empowered to appoint the Chairman of the Committee from amongst its Members.
- The Committee on Public Accounts scrutinizes the Appropriation Accounts

of the Government of India and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

Q.42) (d)

- Delhi and Pondicherry have representation in Rajya Sabha.
- All decisions related to election dispute of MP/MLAs are taken by respective High Court, also appeal against it can be made in the Supreme Court, and the Supreme Court's decision will be final.
- The Parliament consists of the President, Lok Sabha and Rajya Sabha.

Q.43) (a)

- Introduction of separate communal electorates for Muslims- The Indian Councils Act 1909.

Q.44) (d)

- Article 45: The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.
- 11th Schedule the Indian Constitution has a bearing on Education (Education, including primary and secondary schools). It deals with local bodies.
- Seventh Schedule has three lists-
  - The Union list
  - The State list
  - Concurrent list
- Seventh Schedule has provisions related to "education." It comes under the Concurrent list.
- There is no provision for education in fifth schedule of the Indian Constitution.

Q.45) (a)

- Rajya Sabha has power to propose amendments to Money Bill but it is the complete discretion of Lok Sabha whether to accept this proposal or not.

Q.46) (b)

- Preamble: WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
  - JUSTICE, social, economic and political;
  - LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
  - EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all
  - FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
- Article 38- The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.

Q.47) (c)

- Directive principles of state policy guides executive on how to govern.
- Directive Principles of State Policy refers to those principles, which should be kept in mind by the State while formulating policies.
- They are listed in Part IV from Article 36 to Article 51 in our constitution.

Q.48) (c)

- Art 75 (3) says that the Council of Ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha, i.e. Lok Sabha can remove them by passing a no-confidence motion.
- "No confidence motion" itself is not given in the Indian Constitution.
- Rajya Sabha cannot pass cannot remove council of ministers by passing no-confidence motion. So, no confidence motion can be introduced, only in Lok Sabha.

Q.49) (b)

- Estimates Committee is a Parliamentary Committee consisting of 30 members,

elected every year by the lower house of the Parliament - Lok Sabha - from amongst its Members.

- Committee on Public Undertakings has 22 members from both the houses of parliament {15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha}.
- Public Accounts Committee has 22 members of which 15 are from Lok Sabha while 7 from Rajya Sabha.

Q.50) (b)

- The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in the parliament.

Q.51) (c)

Explanation.

- Salient features of the Protection of Human Rights (Amendments) Bill, 2018:
  - It proposes to include "National Commission for Protection of Child Rights" as deemed Member of the National Human Right Commission;
  - It proposes to add a woman Member in the composition of the Commission;
  - It proposes to enlarge the scope of eligibility and scope of selection of Chairperson, National Human Rights Commission as well as the State Human Rights Commission; and
  - It proposes to incorporate a mechanism to look after the cases of human rights violation in the Union Territories.
  - It proposes to amend the term of office of Chairperson and Members of National Human Rights Commission and State Human Rights Commission to make it in consonance with the terms of Chairperson and Members of other Commissions.
- **Benefits:**
  - The Amendment will strengthen the Human Rights Institutions of India further for effective discharge of their mandates, roles and responsibilities.
  - Moreover, the amended Act will be in perfect sync with the agreed global standards and benchmarks towards ensuring the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual in the country.

Q.52) (d)

Explanation.

- It aims at empowering **rural women** through community participation to create an environment in which they can realize their full potential.
- It aims to improve **declining child sex ratio; ensuring survival and protection of the girl child; ensuring her education, and empowering her to fulfill her potential**.
- The Ministry of Women and Child Development is the nodal ministry for this programme.
- It will be implemented through the State Government /UT Administration with a cost sharing ratio of 60:40 between centre and states except for North East & Special Category States where the funding ratio is 90:10.

Q.53) (b)

Explanation

- The Ministry of Women and Child Development is implementing the Swadhar Greh Scheme which targets the **women victims of difficult circumstances** who are in need of institutional support for rehabilitation so that they could lead their life with dignity.
- The Scheme envisages providing shelter, food, clothing and health as well as economic and social security for these women.
- Under the Scheme, Swadhar Greh will be set up in every district with capacity of 30 women. Women victims includes- survivors of natural disasters, prisoners released from jail, victims of domestic violence and Trafficked women/girls rescued.

- The scheme primarily focuses on restoring dignity in life of women.

Q.54) (b)

Explanation

- The report has been developed by NITI Aayog, with technical assistance from the **World Bank**, and in consultation with the **Ministry of Health and Family Welfare** (MoHFW).
- States and UTs have been ranked in three categories namely, Larger States, Smaller States, and Union Territories (UTs), to ensure comparison among similar entities. The Health Index is a weighted composite Index, which for the larger States, is based on indicators in three domains: (a) **Health Outcomes** (70%); (b) **Governance and Information** (12%); and (c) **Key Inputs and Processes** (18%), with each domain assigned a weight based on its importance.
- Among the Larger States, Kerala, Punjab, and Tamil Nadu ranked on top in terms of overall performance, while Jharkhand, Jammu & Kashmir, and Uttar Pradesh are the top three ranking States in terms of annual incremental performance.
- Among Smaller States, Mizoram ranked first followed by Manipur on overall performance, while Manipur followed by Goa were the top ranked States in terms of annual incremental performance.
- Among UTs, Lakshadweep showed both the best overall performance as well as the highest annual incremental performance.

Q.55) (a)

- Members of the Forum will include Secretaries of Ministries of Road Transport & Highways, Railways, Power, Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New & Renewable Energy, Health & Family Welfare, Human Resource Development, Environment, Forest & Climate Change.
- Chief Secretaries of Northeastern states of Assam, Sikkim, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram will also be members of the Forum.
- The first meeting of the newly constituted 'NITI Forum for North East' was held in **Agartala**, Tripura.

Q.56) (a)

Explanation.

- The app which is called UPaAI (unified planning and analysis interface) or 'Solution' will give an integrated platform for data on infrastructure and social indices for each constituency.
- Along with this, the app will also provide information on about 50 Central schemes and MP local area development (MPLAD) fund.
- UPaAI is being developed by **non-profit swaniti initiative** and **Ank Aha** and is being monitored by PMO.

Q.57) (d)

Explanation

- In case of appointment of Judge of Supreme Court other than Chief Justice, the **Chief Justice of India shall always be consulted** in such appointments. As mentioned in Proviso clause of Article 124 (2).
- A distinguished Jurist in the opinion of the **President** can be appointed as Judge of Supreme Court as per **Article 124 (3) (c).**
- Form of oath and affirmation to be made by Judges of Supreme Court has been provided in the **Third Schedule.**

Q.58) (c)

Explanation

- It comes under the aegis of Ministry of Commerce & Industry.
- Quality Council of India (QCI) was set up jointly by the Government of India and the Indian Industry represented by the three premier industry associations to establish and operate national accreditation structure and promote quality through National Quality

Campaign. These industry associations are:

- Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM),
- Confederation of Indian Industry (CII) and
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

- The Council plays a pivotal role at the national level in propagating, adoption and adherence to quality standards in all important spheres of activities including education, healthcare, environment protection, governance, social sectors, infrastructure sector and such other areas of organized activities that have significant bearing in improving the quality of life and well-being of the citizens of India.

Q.59) (a)

Explanation:

- NCVT recognizes training institutions **run by government or by private agencies (not only by private agencies)** for purposes of the grant of National Trade Certificates and lay down conditions for such recognition.
- The National Council for Vocational Training, an advisory body, was set up by the Government of India in 1956 (the then National Council of Training in Vocational Trades - NCTVT).
- The Council has been entrusted with the responsibilities of prescribing standards and curricula for craftsmen training, advising the Government of India on the overall policy and programmes, conducting All India Trade Tests and awarding National Trade Certificates.

Q.60) (b)

Explanation:

- **Article 90** mentions about Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman. Article 90(a) mentions that – A member holding office as Deputy Chairman of the Council of States shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council.
- The Deputy Chairman of the Rajya Sabha presides over the proceedings of the Rajya Sabha in the absence of the Chairman of the Rajya Sabha.
- He may be removed from office by a resolution of Rajya Sabha moved after fourteen days' notice of the intention to move the resolution and **passed by a majority of all the then members of the House.**

Q.61) (b)

Explanation

- 'Vision Document' for a Digital North East by 2022 aims to enhance peoples' lives by capacity building of government staff and doubling BPO strength in the region.
- The Vision document emphasizes leveraging digital technologies to transform lives of people of the North East and enhance the ease of living.
- However, the document does not pertain to National Register of Citizen for the entire north-eastern region. National Register of Citizen has been made compulsory only for the residents of Assam to facilitate the provisions of the Assam Accord.

Q.62) (b)

- Bombay Prevention of Begging Act, 1959 which also extends to Union Territory of Delhi makes begging a criminal offence. However, Delhi High Court in a recent judgment has decriminalized the act of begging and has held that the Begging Act, 1959 violated Article 14 - equality before law and Article 21 - right to life and personal liberty - of the Indian Constitution.

Q.63) (d)

- Ministry of Housing and Urban Affairs launched the Smart Cities Mission on 25 June 2015.
- The objective is to promote sustainable and inclusive cities that provide core

infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of 'Smart' Solutions. The focus is on sustainable and inclusive development and the idea is to look at compact areas, create a replicable model which will act like a lighthouse to other aspiring cities.

- The Smart Cities Mission is meant to set examples that can be replicated both within and outside the Smart City, catalysing the creation of similar Smart Cities in various regions and parts of the country. Comprehensive development in this way will improve quality of life, create employment and enhance incomes for all, especially the poor and the disadvantaged, leading to inclusive cities.

Q.64) (b)

- An integrated theatre command envisages a unified command of the three Services, under a single commander, for geographical theatres that are of security concern.
- The commander of such a force will be able to bring to bear all resources at his disposal from the Indian Air Force, the Army and the Navy with seamless efficacy.
- The integrated theatre commander will not be answerable to individual Services, and will be free to train, equip and exercise his command to make it a cohesive fighting force capable of achieving designated goals. The logistic resources required to support his operations will also be placed at the disposal of the theatre commander so that he does not have to look for anything when operations are ongoing.

Q.65) (c)

Explanation

- Statement 2 - Article 35A has been added to the Indian Constitution through The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 370 of the Indian Constitution and not through an amendment under Article 368 of the Constitution.
- Statement 4 - Supreme Court in the case of Kesavananda Bharati v State of Kerala held that amending power of Parliament cannot be exercised by the Parliament in such a manner so as to destroy the BASIC or FUNDMENTAL FEATURES of the Constitution.
- Some of the features regarded by the Court as Basic/fundamental and hence non-amendable are:

- Supremacy of the constitution
- Republican and Democratic form of Government
- Secular Character of the Constitution
- Separation of power between – legislature, executive and judiciary
- Federal Character of the constitution

- The Court also held that the list of basic features was not an exhaustive list and things can be added by Supreme Court if required. Thus, in the case of Minerva Mills, three more basic features were added –

- Dignity of an individual secured by various fundamental rights and the mandate to build a welfare state contained in the Directive Principle of State Policy.
- Unity and integrity of the nation
- Parliamentary System

Q.66) (b)

Explanation:

- The **Indradhanush (Rainbow) plan** focusses on bringing about systemic changes in the governance of Public Sector Banks (PSBs). The 7 elements of this plan are:
  1. Appointments
  2. Bank of Board Bureau
  3. Capitalization
  4. De-Stressing Public Sector Banks (Addressing NPAs Problem)
  5. Empowerment
  6. Framework of accountability
  7. Governance Reforms

- Also, we should know about the **Mission Indradhanush (Rainbow) which is different from the *Indradhanush (Rainbow) plan.***
- The **Mission Indradhanush** aims to cover all those children by 2020 who are either unvaccinated, or are partially vaccinated against seven vaccine preventable diseases which include **diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis, measles and hepatitis B.**

Q.67) (b)

Explanation:

- Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan, also known as Ayushman Bharat or the National Health Protection Mission (AB-NHPM) will provide free coverage of upto Rs 5 lakh per family per year at any government or even empanelled private hospitals all over India.
- One area of concern with this scheme has been the **exclusion** of outpatient expenses from the scope of AB-NHPM in the initial stages.
- The government has said that OPD that includes minor surgeries not requiring hospitalisation, diagnostic tests and consulting fees, may be covered in the future.

Q.68) (c)

Explanation:

- The National Health Policy, 2017 (NHP, 2017) seeks to reach everyone in a comprehensive integrated way to move towards wellness. It aims at achieving universal health coverage and delivering quality health care services to all at affordable cost.
- This Policy looks at problems and solutions holistically with private sector as strategic partners. It seeks to promote quality of care, focus is on emerging diseases and investment in promotive and preventive healthcare.
- Policy envisages providing larger package of assured comprehensive primary health care through the Health and Wellness Centers'. This policy denotes important change from very selective to comprehensive primary health care package which includes geriatric health care, palliative care and rehabilitative care services.

Q.69) (b)

Explanation:

- EK duniya anEK awaaz (EDAA) – **One World, Many Voices** is a web based free and open audio content and resource exchange platform for community radio broadcasters in **South Asia**.
- It aims to facilitate the meaningful utilisation of resources while breaking the geographical boundaries.
- It is conceptualised, powered and anchored by **OneWorld South Asia.**
- The EDAA platform is catalysed, coordinated and supported by the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.
- **Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA**) is a **strategic partner**.

Q.70) (b)

Explanation:

- **Asian premium** refers to the concept that the countries of the **Asian continent** are required to **pay higher** for the import of crude from OPEC as compared to the rich Western countries – the US and European nations.
- The Indian government will be raising this issue in the meeting of the International Energy Forum.
- **International Energy Forum:** The International Energy Forum (IEF) aims to foster greater mutual understanding and awareness of common energy interests among its members.
- The 72 Member Countries of the Forum are signatories to the IEF Charter, which outlines the framework of the global energy dialogue through this inter-governmental arrangement.
- Covering all six continents and accounting for around 90% of global supply and demand for oil and gas, the IEF is unique in that it comprises not only consuming and producing

countries of the IEA and OPEC, but also Transit States and major players outside of their memberships, including Argentina, China, India, Mexico, Russia and South Africa.

- The Forum's biennial Ministerial Meetings are the **world's largest gathering of Energy Ministers.**
- The IEF and the global energy dialogue are promoted by a permanent Secretariat of international staff based in the **Diplomatic Quarter of Riyadh, Saudi Arabia.**
- OPEC- The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) was founded in Baghdad, Iraq, with the signing of an agreement in September 1960 by five countries namely Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. They were to become the Founder Members of the Organization.
- The OPEC Secretariat is the executive organ of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). It is located in Vienna; it also functions as the Headquarters of the Organization.

Q.71) (b)

- It is the mandate of National Commission for Protection of Child rights (NCPCR) to monitor the setting up of special courts in the state.
- The POCSO Act defines a "child" as a person under the age of 18. Unlike rape laws, POCSO is gender neutral. Hence, both **men and women** can be prosecuted for offences under the Act, for offences against boys and girls.

Q.72) (b)

Explanation:

- 'Prisons' is a State subject under List-II or State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India. The management and administration of Prisons falls exclusively in the domain of the State Governments.

Q.73) (d)

Explanation:

- The Representation of People's (Amendment) Act, 2010 gave for the first time, provision of voting to non-resident Indians. But it did not give them the right to vote in absentia, they were required to be physically present in their respective constituencies at the time of elections.
- The 2017 Bill seeks to amend the 1951 Representation of people's Act to permit an overseas voter /Non-resident Indian to cast their vote *in person or by proxy* in the constituency where the poll is taken. Such a right is only available to an NRI and not an ordinary resident Indian citizen.
- The Bill also aims to make certain provisions of the Act more gender neutral by replacing the word "wife" with "spouse".

Q.74) (a)

Explanation :

- The Economist Intelligence Unit (EIU) publishes an annual Global Liveability Ranking, which ranks 140 cities for their urban quality of life based on assessments of stability, healthcare, culture and environment, education and infrastructure. Only two Indian cities, Delhi and Mumbai were included in the annual index. Vienna, Austria s capital was ranked number one.

Q.75) (d)

- The central government can decide the manner in which the statistical information/date can be used. The amendment to the Act has extended the Act to the state of Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir State Legislature enacted the Jammu and Kashmir Collection of Statistics Act, 2010, which extends to the whole of Jammu and Kashmir and is almost a replica of the Central legislation. The Collection of Statistics Act, 2008, and the Jammu and Kashmir Collection of Statistics Act, 2010, were not applicable to statistical subjects falling in the Union List, as applicable to Jammu and

Kashmir under the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954.

- This had created a legislative vacuum. Moreover, the concurrent jurisdiction to be exercised by the Centre in Jammu & Kashmir had also not been provided for in the Collection of Statistics Act, 2008.

The amendment statute filled the vacuum.